नई सोच • नई शुरूआत • नया भारत

अनप्लग इंडिया

सच की आवाज, भारत की पहचान

नोएडा एनसीआर संस्करण

वर्ष : 01 | अंक : 35 | नोएडा, बुधवार, 4 नवम्बर, 2026 | Website: www.unplugindia.com | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 03 रुपए

आज का विचार

'उगता सूरज यह नहीं पूछता कि कल बादल थे या नहीं, वो बस चमकता है. '



पंजाब में अकाली-बीजेपी गठबंधन लगभग तय!

- दीवाली के बाद लगेगी मुहर दोनों पार्टियां हैं तैयार

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच दोनों पूर्व एनडीए सहयोगियों के बीच गठबंधन पर अंतिम फैसला दीवाली के आसपास होने की उम्मीद



है। पीएम मोदी खुद इस गठबंधन को लेकर ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि इस घोषणा को एक ऐतिहासिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बठिंडा में एक विशाल रैली कराने की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली में पीएम मोदी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर ऐलान कर सकते हैं। हालांकि, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों की मानें तो बीजेपी 45 से 50 सीटों पर समझौता कर सकती है।

अमित शाह से मिले चिरंजीवी व राम चरण

- बोले-एआई और डीपफेक तकनीक से कलाकारों को खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी और उनके बेटे राम चरण ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों कलाकारों ने फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल



इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए सरकार की ओर से सख्त नियम और कड़े दंड का प्रावधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही लिखित आवेदन जमा करने की सलाह दी।

त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों पर तस्करों ने किया हमला

- 3 घायल, अब तक 8 गिरफ्तार ढाई साल में ऐसी 3 घटनाएं



अगरतला (एजेंसी)। त्रिपुरा के आशाबाड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट के पास सोमवार को कुछ तस्कर अवैध सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बीएसएफ की 49वीं बटालियन के जवानों ने उनका पीछा किया और एक संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी पहचान हिफजुर रहमान के रूप में हुई है। इसी दौरान रहीमपुर कांतामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट से बीएसएफ के 3 जवान गाड़ी से बॉक्सानगर जा रहे थे। रास्ते में तस्करों के एक समूह ने उन्हें घेरकर हमला कर दिया। हमलावरों ने जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम माणिक साहा ने घटना की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हमारा अखबार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। त्रिपुरा में इस घटना के साथ बीएसएफ जवानों पर हमले की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अप्रैल 2024 में दुर्गापुर गांव में तस्करी रोकने पर भीड़ ने जवानों पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। वहीं, नवंबर 2025 में बिशालगढ़ में संदिग्ध पशु तस्करों को रोकने पर भीड़ ने बीएसएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी।

एक जगह अनिश्चितकाल तक धरना नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट बोला-प्रदर्शन एक का नहीं,सबका अधिकार

कहा-रोजगार और कारोबार का ध्यान रखना भी है जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों, लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ व्यापारियों की याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुनवाई की। भारत के



- दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को लेकर सीजेआई की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते।

अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे। हर किसी को विरोध करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों और अन्य लोगों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन की सुनवाई के दौरान आई, जब उस जगह से विरोध प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में व्यापारिक संगठनों ने याचिका दायर की, जिसमें बताया कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने व्यापारियों के संगठनों से कहा है कि वे एंटी-सरकार विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं। विरोध प्रदर्शन के चलते व्यापारियों की स्थिति बताते हुए उनके वकील ने कोर्ट से कहा, विरोध स्थल के आस-पास के इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं। सभी दुकानें बंद हैं और आज कनॉट प्लेस में कोई नहीं है।

सरकार के शीर्ष वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो कोई भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे अपने कार्यों के नतीजों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

व्यापारियों ने कहा-त्योहारों में 2000 करोड़ का नुकसान

सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। त्योहारों के सीजन में दुकानें बंद रहीं और बिक्री घट गई। उन्होंने दावा किया कि कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर त्योहारों के सीजन में बिक्री नहीं होगी तो व्यापारियों और उनसे जुड़े लोगों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कोर्ट से अगले दो महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन या धरने पर रोक लगाने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिन तक वहां बैठे रहे। मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया। संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो संगठन बंद या प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

मोदी बोले-पहले गरीबी खत्म करने के वादे होते थे,अब जमीनी स्तर पर काम हो रहा

छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियों ने गरीबी खत्म करने के वादे सुने हैं। पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए जमीन पर काम हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो की करीब 21,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आज दुनिया में भारत की चर्चा दो और वजहों से हो रही है। पहली, दुनिया में मुश्किल हालात के बावजूद भारत सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। दूसरी, सिर्फ 10 से 12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है।



महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं

महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण के लिए काम हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हुआ है। इस मुश्किल समय में एनडीए सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। देश के सैकड़ों छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ इस साल फरवरी में अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार इस फंड के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे रही है। पुणे मेट्रो लाइन का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से हुआ है।

अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है सरकार

21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल,दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार पहले बैच के कुछ अग्निवीरों की चार साल की सेवा पूरी होने के बाद एक्सटेंशन देने पर विचार कर रही है। यह उन अग्निवीरों के अलावा होगा, जिन्हें स्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाएगा। पहले बैच की चार साल की सेवा 21 नवंबर को खत्म होगी। इससे पहले स्थायी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और एक्सटेंशन के प्रस्ताव पर फैसला होने की उम्मीद है। सोमवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ दिनों में कई हाईलेवल बैठकें हो चुकी हैं। अभी सरकार ने कोई फैसला घोषित नहीं किया है। प्रस्तावित एक्सटेंशन कितने समय का होगा, यह अभी साफ नहीं है। अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत तीनों सेनाओं के अन्य रैंक में युवाओं की चार साल के लिए भर्ती की जाती है।



जेन-जी आंदोलन पर सुनील आंबेकर बोले-देशहित में होना चाहिए

आरएसएस के 3 साल का एजेंडा तय, 5 मुद्दों पर फोकस

इंदौर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले तीन साल सामाजिक समरसता, पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली, कुटुंब प्रबोधन, स्व का भाव और नागरिक कर्तव्य जैसे पांच विषयों पर फोकस करेगा। संघ ने इन्हें पंच परिवर्तन नाम दिया है। शताब्दी वर्ष के दौरान इन विषयों को समाज तक पहुंचाने के लिए गृह संपर्क अभियान, सम्मेलन और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर में सोमवार को शुरू हुई अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक में इन कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन हुआ। बैठक के बाद अखिल भारतीय



प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने जेन-जी आंदोलन से जुड़े सवाल पर कहा कि देश में कोई आवाज उठाता है तो संघ को पक्ष-विपक्ष के नजरिए से क्यों देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन देशहित में हो। संघ इस विषय में सतर्क रहता है और आगे भी रहेगा।

महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर चर्चा

शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी रही। बैठक में इस अनुभव के आधार पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों और उपक्रमों पर विचार किया गया। युवाओं को जोड़ने के लिए शहरों, गांवों और कॉलेज कैंपस में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अन्य युवाओं ने हिस्सा लिया था। बैठक के एजेंडे में युवाओं में नशीली दवाओं के बढ़ते चलन पर चिंता और इससे निपटने के प्रयास भी शामिल रहे। आंबेकर ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रयास जरूरी हैं।

देशभर में 1.01 लाख से ज्यादा दैनिक शाखाएं

आंबेकर के मुताबिक, देशभर में संघ की दैनिक शाखाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख 1 हजार 151 हो गई है। साप्ताहिक और मासिक मिलन को मिलाकर संघ का काम 1 लाख 10 हजार 849 स्थानों तक पहुंच गया है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में शताब्दी वर्ष के दौरान 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं जुड़ी हैं। बैठक में शाखाओं के विस्तार के प्रयासों और उनके परिणामों की समीक्षा की गई। शाखाओं के साथ साप्ताहिक और मासिक मिलन की गतिविधियों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला, एक की मौत

14 भारतीय सवार थे,13 इंडियनों को बचाया गया

ओमान (एजेंसी)। होर्मुज स्ट्रेट में 2 नवंबर को एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ। इसमें गुजरात के एक नाविक की मौत हो गई। जहाज पर सवार बाकी 13 भारतीयों को ओमान के कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। मृतक की पहचान गांधार नाहीम अजीज के रूप में हुई है। जहाज का नाम अल जुसुफी है। हमला कैसे हुआ और किसने किया इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।



हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही और कारोबार बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले हुए। ईरान-अमेरिका जंग शुरू होने के बाद एक महीने में हमलों की यह सबसे बड़ी संख्या थी।

पहले भी भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमला हुआ था

होर्मुज स्ट्रेट में इससे पहले 29 अक्टूबर को भारतीय नाविकों वाले जहाज को निशाना बनाया गया था। 27 भारतीय क्रू सदस्यों वाले तेल टैंकर लुईस 1 पर हमला हुआ था। पनामा के झंडे वाले इस जहाज के पास एक छोटी नाव आई थी। उसमें सवार लोगों ने जहाज के बाहरी हिस्से पर दो विस्फोटक चिपका दिए थे और वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों विस्फोटकों में धमाका हुआ। इससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई और इंजन कुछ समय के लिए बंद हो गया। हालांकि, क्रू ने आग पर काबू पा लिया।



श्रीनगर से सांसद मेहंदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी

जनसभा में सांसद पद से इस्तीफे का किया ऐलान

श्रीनगर (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संसद की सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान किया। मंगलवार

- 24 विधायक भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं

को बडगाम में जनसभा करके उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। रूहुल्लाह ने कहा- यह आजादी का फैसला है। मैं एक शहीद की विरासत और पाक खून की नस्ल का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपनी आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आज दोपहर 2.40 बजे से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस



का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने बडगाम में पिता आगा सैयद मेहंदी की 26वीं पुण्यतिथि पर जनसभा बुलाई थी। रूहुल्लाह ने बताया कि वे अपना इस्तीफा मुहम्मद अशरफ मट्टू के जरिए पार्टी को भेजेंगे। उन्होंने पार्टी पर लोगों की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया।

प्रदूषण फैलाने व नियमों का उल्लंघन करने पर निगम ने 1600 चालान काटे

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रेप-2 लागू हो चुका है। इसके मद्देनजर निगम प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बीते दो दिनों में 1600 से अधिक चालान काटे हैं। इसके तहत निगम ने सोमवार को सुबह और रात के समय निगरानी व जांच करते हुए 798 चालान काटे और मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर तक 800 से अधिक चालान काटे। निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम के सभी बारह जोन में एक हजार से अधिक सिविल डिफेंस वॉलिंटियरों की तैनाती की गई है। यह लगातार निगरानी करते हुए सभी जोन में नजर रखे रहे हैं। इसके तहत निगम प्रशासन ने तीन सौ से अधिक टीमों का भी गठन किया गया। निगम प्रशासन द्वारा ग्रेप-2 की पाबंदियों व नियमों और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर प्रदूषण फैलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दो हजार, पांच हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के चालान काट रहा है।

निगम अधिकारियों के अनुसार अपशिष्ट व बायोमास को खुले में जलाने, सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट व बायोमास जलाने पर, निर्माणाधीन सामग्री को अव्यवस्थित तरीके से सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर फैलाने व नियमों का उल्लंघन करने, निर्माणाधीन सामग्री को नियमों के मद्देनजर न ढकने जैसे नियमों व ग्रेप-2 की पाबंदियों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों ने मंगलवार को मध्य जोन में 173 मध्य उत्तरी जोन में 109, उत्तर पश्चिमी जोन में 199, दक्षिण पश्चिमी जोन में 116 और दक्षिण पूर्वी जोन में 194 चालान कार्रवाई कर काटे हैं।

मोरी गेट से सात हजार किलो खोया जब्त कर नष्ट किया

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दीपावली के मौके पर मिठाई बेचने के लिए तैयार किए गए मिलावटी और अस्वच्छ खोये की बड़ी खेप को खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त कर नष्ट किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में सुबह छापेमारी की। इस दौरान लगभग 7,000 किलो अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया जब्त कर उसे नष्ट किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मोरी गेट स्थित खोया मंडी में लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में खोया यहां से दुकानदारों को बेचा जाता है। इस त्योहारी सीजन में चौथी बार मोरी गेट स्थित खोया मंडी में विभाग ने छापेमारी की। टीम ने मोरी गेट की खोया मंडी से 44 निगरानी नमूने एकत्र किए। इनकी मौके पर ही 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' मोबाइल टेस्टिंग सुविधा के माध्यम से प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें 35 नमूने जांच में फेल पाए गए। इसके अलावा दो अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध सामग्री में दूध पाउडर, वनस्पति और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों से संबंधित जानकारी सामने आई है। इन सामग्रियों के संबंध में आगे की जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की सतर्कता, मेहनत और समय पर की गई कार्रवाई से मिलावट जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। उन्होंने टीम को आगे भी इसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की खुशियों में मिलावट करने वालों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और मिलावटखोरों के विरुद्ध दिल्ली सरकार की कार्रवाई आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया है। विभाग की ओर से अब तक की गई कार्रवाई के तहत चार सितंबर को 2,830 किलो खोया, आठ सितंबर को 610 किलो खोया और 23 अक्तूबर को 520 किलो खोया नष्ट किया गया। इसके बाद तीन नवंबर को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में कार्रवाई करते हुए लगभग 7,000 किलो अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया नष्ट किया गया। इस तरह विभाग अब तक कुल 10,660 किलो खोया नष्ट करा चुका है।

ऐप आधारित बसों का किराया महंगा, सुविधाएं कम

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली में मोबाइल ऐप आधारित बसों में महंगा किराया देने के बावजूद सुविधाएं कम है। सीट बुकिंग करने के बाद अगर बोर्डिंग लोकेशन अलग है तो दिक्कतें और बढ़ जाती है। यात्रियों का कहना है कि बसों की लाइव लोकेशन न मिल पाने के कारण अक्सर पिकअप प्वाइंट पर लंबा इंतजार करना पड़ता है। लंबी दूरी की इन बसों का सफर अक्सर रात का होता है, ऐसे में रात को पिक अप प्वाइंट पर इंतजार करना और मुश्किल और चुनौती भरा हो जाता है। दिवाली और छठ मनाने के लिए दिल्ली में रह रहे यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार के प्रवासी लोग अब गांव लौट रहे हैं। ट्रेनों में कंफर्म टिकट न मिलने के कारण ऐप आधारित बसों के संचालकों की चांदी हो रही है। आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और दिल्ली के अन्य अलग-अलग इलाकों से सफर शुरू करने वाली इन बसों में सीटें तो ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, लेकिन दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहने वाले यात्री रोहणी, पश्चिम विहार, द्वारका से सफर शुरू करते हैं। ऐप आधारित लग्जरी बस से हल्द्वानी जाने के लिए आनंद विहार पहुंचे यात्री शिवांश ने बताया कि पहले उन्होंने गाजियाबाद से पिकअप प्वाइंट तय किया था, लेकिन कोई समस्या न हो इसके चलते बाद में आनंद विहार से ही बस में सवार होने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जहां ट्रेन से स्लीपर श्रेणी का किराया महज 250 रुपये और थर्ड एसी बर्थ का किराया करीब 550 रुपये है, वहीं एसी बस में 1000 रुपये में सीट मिली है। वहीं, बस मैनेजर ने बताया कि दिल्ली से हल्द्वानी तक अगर शेयरिंग स्लीपर सीट बुक करेंगे तो 900 रुपये और अलग बर्थ बुक करने पर 1000 रुपये किराया देना होगा। यात्रियों ने बताया कि ऐप आधारित बसों में सीट बुक कराने के बाद अगर कैंसल करानी पड़ी तो फिर रिफंड मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाली आकांक्षा ने बताया कि त्योहारों पर घर आगरा जाने के लिए उन्होंने पहले एसी बस से एक नवंबर के लिए सीट बुक कराई थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण बुकिंग दो दिन पहले निरस्त करनी पड़ी। 50 फीसदी किराया रिफंड मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। वहीं, अब दोगुना किराए पर दोबारा सीट बुक करनी पड़ी।

महिला सशक्तीकरण पर विचार रखेंगे विद्यार्थी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में तीसरी से बारहवीं तक के विद्यार्थी महिला सशक्तीकरण पर अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। बेटियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सीबीएसई महिला सशक्तिकरणः शिक्षित बने, सक्षम बने थीम पर एक अभिव्यक्ति शृंखला आयोजित करने जा रहा है। इसका आयोजन स्कूल व राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को निबंध और कविता के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे स्कूल स्तर पर यह गतिविधियां पांच नवंबर से 17 नवंबर तक आयोजित करें। विद्यार्थियों को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुच्छेद, निबंध अथवा कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। प्रतियोगिता को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तीसरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थी 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखेंगे। छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 400 शब्दों में निबंध या कविता लिखनी होगी। नौवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 700 शब्दों में निबंध या कविता लिखनी होगी। जबकि ग्यारहवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए 1000 शब्दों का निबंध या कविता निर्धारित की गई है। विद्यालय स्तर पर प्राप्त एंट्री का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक श्रेणी से एक श्रेष्ठ एंट्री का चयन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय अधिकतम चार एंट्री सीबीएसई को भेज सकेगा। स्कूलों को चयनित एंट्री को 18 से 25 नवंबर तक सीबीएसई के एक्सप्रेशन सीरीज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोर्ड के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र से हर श्रेणी की 10 सर्वश्रेष्ठ एंट्री का चयन राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं के चयन के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को ऑनलाइन मेरिट प्रमाणपत्र दिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नकल या साहित्यिक चोरी वाली एंट्री स्वीकार नहीं की जाएंगी।

दीपावली से पहले देशभर में सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने बाजारों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई चौकसी

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने देशभर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा, निगरानी और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। खरीदारों और आने-जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली में एसीपी सोनू कुमार और सदर बाजार एसएचओ सहदेव सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और भीड़भाड़ वाले सदर बाजार इलाके में गश्त की। कुमार ने बताया कि दीपावली के चलते बाजार में भारी भीड़ है और देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। इस बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।

उन्होंने कहा, 'दीपावली की वजह से बाजार में बहुत भीड़ है। लोग देश भर से यहां खरीदारी करने आ रहे हैं, जिससे यहां काफी भीड़ हो गई है। हम स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमने बाजार के सभी



प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है।'

उन्होंने बताया कि खरीदारों की आवाजाही सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है और अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही अहम जगहों पर ऊंचे निगरानी प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं।

कुमार ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी भीड़ ज्यादा देर तक एक जगह जमा न रहे। बाजार के मुख्य स्थानों, जैसे कुतुब चौक और अन्य चौराहों पर 'फेशियल रिकग्निशन सिस्टम' से लैस वैन तैनात की गई हैं। इसके अलावा, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्तों की मदद से नियमित जांच भी की जा रही है।'

उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन से पहले पुलिस ने बाजार कल्याण संघों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें करके सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की थी। व्यापारियों से कहा गया है कि वे अपने निगरानी उपकरणों (जैसे सीसीटीवी) को चालू रखें और जहां जरूरत थी, वहां अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं।

बाजारों में खाकी और कैमोफ्लाज वर्दी पहने पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कई टीमें ट्रैफिक को नियंत्रित करने और खरीदारों की आवाजाही पर नजर रखने का काम कर रही हैं।

इस बीच, रेलवे प्रशासन ने भी दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और स्टेशन पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सिटी पुलिस कमिश्नर शेखर देशमुख ने बताया कि दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि त्योहार की खरीदारी के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों के बाजारों में आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए पुलिस ने निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन के उपायों को तेज कर दिया है। बाजारों में चोरी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए विशेष अपराध रोकथाम टीमें तैनात की गई हैं। पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की जांच के लिए पॉइंट और पुलिस सहायता बूथ भी बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ को रोकने और रोजमर्रा के ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने के लिए किए गए इंतजामों की नियमित समीक्षा की जा रही है।

कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति में वे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 के जरिए पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी।

त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों, ट्रांसपोर्ट हब और व्यावसायिक इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए, पुलिस और रेलवे प्रशासन ने आपसी तालमेल बढ़ाया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट-कृषि भवन में मौजूद मस्जिद हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके। सरकार का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। सरकार ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है।

सरकार ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद मस्जिद को हटाना जरूरी है।

केंद्र ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि कृषि भवन के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को



नमाज की पूरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में कृषि भवन परिसर के भीतर अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसे कृषि भवन परिसर या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परिसर के भीतर इस मस्जिद के लिए कोई अलग जगह आवंटित या निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र में धार्मिक स्थल के लिए अलग से जगह देना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार कई पुराने भवनों को हटाकर नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों का निर्माण कर रही है। इसी योजना के तहत कृषि भवन परिसर भी पुनर्विकास के दायरे में आता है।

नीट-पीजी 2025

सुप्रीम कोर्ट में कट-ऑफ घटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-पीजी 2025 परीक्षा के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल घटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। नीट-पीजी 2025 परीक्षा को लेकर मंगलवार को 12 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की गई। विशेषज्ञ समिति ने बताया कि 2027 से नीट-पीजी और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) के लिए पर्सेंटाइल-आधारित प्रणाली को रैंक-आधारित प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। कोर्ट को बताया गया कि समिति की चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल खाली सीटों को भरने के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम योग्यता मानकों में ढील नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपने का निर्देश दिया। कमेटी की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करेंगे।

बता दें कि नीट-पीजी परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया जाता है। नीट-पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त 2025 को एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 3 सितंबर 2025 को घोषित कर दिया गया था।



एनबीईएमएस की ओर से नीट-पीजी 2025 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2025 को जारी किए गए थे। वहीं, उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर चुनने और उसमें सुधार करने के लिए विंडो 13 से 17 जून 2025 तक आधिकारिक पोर्टल पर सक्रिय थी।

एनबीईएमएस की ओर से देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी) और पीजी डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता और रैंकिंग निर्धारित करने के लिए नीट-पीजी परीक्षा आयोजित की जाती है।

दिल्ली के प्रदूषण पर 'आप' का भाजपा पर पलटवार, कहा- अपनी नाकामी छिपाने के लिए पंजाब के किसानों को कर रही बदनाम

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली में जहरीली होती हवा के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराने वाले मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए पंजाब के किसानों को बदनाम कर रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है तो फिर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने में भाजपा सरकार क्यों नाकाम साबित हो रही है? आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ मिलकर पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 90 से 95 प्रतिशत तक की कमी की है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले पराली जलाने के करीब 71 से 80 हजार मामले सामने आते थे, जबकि पिछले साल इनकी संख्या घटकर लगभग पांच हजार रह गई थी। इस साल अब तक केवल एक हजार मामले सामने आए हैं। ऐसे में भाजपा को पंजाब के किसानों पर आरोप लगाने के बजाय दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए किए गए अपने कामों का हिसाब देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों को कम दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल सात और इस साल 13 नए प्रदूषण निगरानी स्टेशन लगाए हैं, जबकि पहले से दिल्ली में 39 स्टेशन थे। इसके अलावा 20 नए मॉनिटरिंग स्टेशन हरे-भरे इलाकों में लगाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, इन स्थानों पर अपेक्षाकृत कम प्रदूषण दर्ज होने से दिल्ली के औसत एक्यूआई को कम दिखाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान प्रदूषण कम करने के बजाय आंकड़ों को बेहतर दिखाने पर है।

उन्होंने पिछले साल आनंद विहार और द्वारका के प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किए जाने का भी आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण की समस्या का वास्तविक समाधान निकालने के बजाय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कृत्रिम बारिश (आर्टिफिशियल रेन) कराने की भाजपा सरकार की घोषणा पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार के संबंधित विभाग ने दिल्ली में उस मौसम के दौरान कृत्रिम बारिश की संभावना नहीं होने की जानकारी दी थी, इसके बावजूद इस योजना पर पैसा खर्च किया गया। उन्होंने पूछा कि इस खर्च की जवाबदेही कौन लेगा?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार पंजाब का नाम ले रही है। उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी स्थिति उस बच्चे जैसी है, जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और परीक्षा में असफल होने पर पड़ोसी बेंच पर बैठे बच्चे को जिम्मेदार ठहरा रहा है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि वर्ष 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के समय पराली जलाने की घटनाएं काफी अधिक थीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ संवाद और सहयोग के जरिए इन घटनाओं को कम करने के लिए काम किया। उनके अनुसार, पिछले साल पंजाब में पराली जलाने के मामले पांच हजार से भी कम रह गए थे और इस साल इनकी संख्या लगभग एक हजार तक पहुंच गई है।

चीन ने सुरंग निर्माण मशीनें रोकीं तो भारत खुद बनाएगा, विकास नहीं रुकेगा: पीयूष गोयल

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि यदि चीन भारत को टनल-बोरिंग मशीन (टीबीएम) की आपूर्ति रोक देता है, तो भारत स्वयं इस तकनीक का विकास करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने रणनीतिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित यंग लीडर्स डिस्कोर्स फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत किसी भी महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच के लिए दूसरे देशों से रियायतें मांगने या अपने हितों से समझौता करने वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर वे हमें टनल-बोरिंग मशीन नहीं देंगे, तो हम उसे भारत में ही विकसित कर लेंगे। भारत ऐसा देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए।' गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत के विकास की राह में आने वाली कोई भी बाधा देश की प्रगति को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा, 'भारत की प्रगति की यात्रा में चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी की जाएं, हम हर बेड़ी को तोड़ सकते हैं।' कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने छात्रों के साथ देश के आर्थिक विकास, उभरते अवसरों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि छात्रों ने भारत की विकास यात्रा और उसमें युवाओं के योगदान से जुड़े कई महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल पूछे। गोयल ने कहा कि भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी के पास इस परिवर्तन में सार्थक योगदान देने के अनेक अवसर हैं। उन्होंने छात्रों की जिज्ञासा और देश के भविष्य के प्रति उत्साह की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने छात्र जीवन से जुड़ा एक हल्का-फुल्का प्रसंग भी साझा किया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में छुट्टी की घोषणा से बड़ी खुशी कोई नहीं होती थी। मुंबई में अपने छात्र जीवन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश और जलभराव के कारण स्कूल-कॉलेज बंद होने की उम्मीद विद्यार्थियों को बेहद उत्साहित करती थी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब विदेशी निर्भरता खत्म करना है: राजनाथ सिंह

अनप्लग इंडिया

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब हर चीज का निर्माण देश में करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि देश की महत्वपूर्ण रक्षा जरूरतें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहें। आत्मनिर्भरता का असली उद्देश्य तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है, ताकि भारत अपनी जरूरतों के अनुसार रक्षा तकनीक विकसित कर सके और उसमें लगातार सुधार भी कर सके। राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आयोजित 'दिल्ली डिफेंस डायलॉग' 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी रक्षा उपकरण या प्रणाली का देश में केवल निर्माण या तैयार कर लेना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। असली आत्मनिर्भरता तब हासिल होगी, जब भारत के पास उसे डिजाइन करने का ज्ञान, निर्माण की तकनीक, उसमें सुधार करने के अधिकार और उसके पूरे जीवनकाल तक रखरखाव करने की क्षमता भी हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में ऐसा माहौल तैयार



करने की जरूरत है, जिसमें नए विचार तेजी से प्रयोग, विकास और फिर सेना के इस्तेमाल तक पहुंच सकें। इसके लिए शोध और विकास के पूरे तंत्र को मजबूत करना होगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन तकनीकी नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल एक संस्था की नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और नए उद्यमों को मिलकर काम करना होगा। इन सभी के सहयोग से ऐसा नवाचार तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जहां नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर और संसाधन उपलब्ध हों। राजनाथ सिंह ने शोध और सेना की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शोध होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नए विचारों पर स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। शोध का उद्देश्य केवल मौजूदा जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि युद्धक्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को भी तलाशना होना चाहिए।

रक्षा मंत्री ने कहा कि नवाचार के लिए प्रयोगों को बढ़ावा देना जरूरी है। हर प्रयोग सफल नहीं होगा, लेकिन हर प्रयोग से कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सफल प्रयोग केवल प्रयोगशालाओं या शुरुआती नमूनों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्हें बड़े स्तर पर उत्पादन और सेना में इस्तेमाल तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा तंत्र बनाना होगा, जहां नए विचारों को प्रोत्साहन मिले, निवेश लगातार जारी रहे और सफल तकनीक को वास्तविक सैन्य क्षमता में बदला जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता की भारत की कोशिश दुनिया से अलग होने की नहीं है। इसके उलट, तकनीकी रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, विकास, निर्माण और नवाचार का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनना होना चाहिए। इसके लिए देश को अपनी तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को लगातार मजबूत करना होगा। उन्होंने रक्षा निर्यात के दायरे को भी व्यापक बनाने की

संक्षिप्त समाचार

दिवाली पर हाईराइज सोसाइटियों में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर रोक की तैयारी



अनप्लग इंडिया

नोएडा। दिवाली से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसाइटियों में अग्नि सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। आवासीय टावरों की बालकनियों में पटाखों और रॉकेट के कारण आग लगने की घटनाओं के बाद कई अपार्टमेंट एसोसिएशन ने आसमान में छोड़े जाने वाले पटाखों पर रोक लगाने या उन्हें हतोत्साहित करने का फैसला किया है। सुपरटेक इको विलेज-1 में पिछले एक साल के दौरान आग की दो घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में टावर बी-16 की दूसरी मंजिल की बालकनी में पटाखा गिरने से वहां रखे सामान में आग लग गई थी। पिछले साल भी एक रॉकेट के एयर कंडीशनिंग यूनिट से टकराने के बाद एक फ्लैट में आग लग गई थी। नोएडा हाईराइज फेडरेशन और नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने भी सोसाइटियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कुछ सोसाइटियां पटाखे जलाने के लिए निर्धारित स्थान बनाने और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने की तैयारी कर रही हैं। पिछली दिवाली के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसाइटियों में 17 आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं।

गाजियाबाद में 11 जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, 5 से 7 नवंबर तक मिलेगी अनुमति



अनप्लग इंडिया

गाजियाबाद। दीपावली से पहले गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त व्यवस्था लागू की है। जिले में केवल 11 निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों पर 5 से 7 नवंबर तक बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस कहीं भी पटाखे बेचने या उनका अवैध भंडारण करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ स्वद्धक्र दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

NCR में लाइसेंस के आधार पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट है। इसके अलावा अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री या अवैध तरीके से भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

तीन जोन में 11 स्थान किए गए निर्धारित

गाजियाबाद को तीन जोन में बांटकर कुल 11 स्थानों पर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस के आधार पर ही दुकानें संचालित की जा सकेंगी। दमकल विभाग की ओर से निर्धारित बिक्री स्थलों पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था भी की गई है।

नगर क्षेत्र में इन तीन जगहों पर बिकेंगे पटाखे
घंटाघर
कविनगर
विजयनगर सेक्टर-9 रामलीला मैदान
ट्रांस हिंडन क्षेत्र में ये तीन स्थान निर्धारित
इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान
साहिबाबाद गोल पार्क रामलीला मैदान
टीला मोड़ स्थित ऑक्सी होम के सामने मैदान
देहात क्षेत्र में इन पांच जगहों पर दुकानें लगेंगी
गढ़ी कटैया नगर पालिका मैदान
लोनी इंटर कॉलेज मैदान
मोदीनगर का चह्न मोदी मैदान
सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान
मुरादनगर चुंगी नंबर-3 रामलीला मैदान

दुकानदारों के लिए अग्नि सुरक्षा के नियम अनिवार्य

पटाखों की दुकान लगाने वाले कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा। दुकानों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने होंगे। प्रशासन ने दुकानों के आकार और उनके बीच की दूरी के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं।

प्रत्येक निर्धारित बिक्री स्थल पर दमकल विभाग की व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं है। बिना लाइसेंस दुकान लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्वद्धक्र दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

91 देशों में गलगोटियास के 1 लाख से अधिक पूर्व छात्र, विद्यार्थियों को मेंटरशिप और नौकरी के अवसरों से जोड़ रहा नेटवर्क

अनप्लग इंडिया।

ग्रेटर नोएडा। गलगोटियास विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेटवर्क वैश्विक स्तर पर लगातार विस्तार कर रहा है। विश्वविद्यालय के अनुसार, उसके एक लाख से अधिक पूर्व छात्र दुनिया के 91 देशों में रहकर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह नेटवर्क अब वर्तमान विद्यार्थियों के लिए मेंटरशिप, इंटर्नशिप, नौकरी और उद्यमिता से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम बन रहा है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2026 को गुरुग्राम में 'समागम' नाम से एलुमनाई मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली-NCR के विभिन्न क्षेत्रों से आए विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय की ओर से इस तरह के आयोजन लंदन, कैम्ब्रिज, सिंगापुर, दुबई और हांगकांग में भी किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और खाड़ी देशों में उसके पूर्व छात्रों की बड़ी संख्या है। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में भी गलगोटियास के पूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय ने लंदन, सिंगापुर, दुबई और हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय एलुमनाई चैप्टर स्थापित किए हैं। वहीं दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और मुंबई में भी पूर्व छात्रों के समूह सक्रिय हैं।

गलगोटियास विश्वविद्यालय के मुताबिक, उसके पूर्व छात्र Google, Microsoft, Apple, Amazon Web Services, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Deloitte, PwC और Tata Consultancy Services जैसी कंपनियों में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। कुछ पूर्व छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इनमें LTIMindtree में जापान के कारोबार का नेतृत्व कर रहे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड तथा Wipro में यूरोप के बड़े कारोबारी सौदों और साझेदारियों का नेतृत्व करने वाले पूर्व छात्र शामिल हैं।

74 कि.मी. लंबा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 3 साल में होगा तैयार, यीडा ने इस कंपनी को सौंपा काम

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले 74.4 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण दो कंपनियां करेंगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे को तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यमुना प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के 24.5 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण की जिम्मेदारी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपी गई है। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। स्याना क्षेत्र से इसका निर्माण शुरू होगा और यीडा क्षेत्र के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी के पास आकर यमुना एक्सप्रेसवे से मिलेगा। यमुना प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र की करीब 92 प्रतिशत जमीन खरीद का काम पूरा कर लिया है। अब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा।



6 लेन का बनेगा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने यीडा क्षेत्र में कार्य के लिए एफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को करीब 2,086 करोड़ रुपये का टेंडर कर दिया है। शेष हिस्से का निर्माण दूसरी कंपनी करेगी। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल्ड सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। छह लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

नोएडा एयरपोर्ट तक आवाजाही सुगम होगी

लिंक एक्सप्रेसवे का उद्देश्य नोएडा एयरपोर्ट को प्रमुख एक्सप्रेसवे और आसपास के औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों से सीधे जोड़ना है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी और आसपास के क्षेत्रों से एयरपोर्ट तक आवागमन आसान होगा।

एस. परमशिवन, प्रबंधक निदेशक, एफकॉन्स, ''इस परियोजना को तय समय पर पूरा करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यीडा क्षेत्र का हिस्सा पूरा होने में करीब तीन वर्ष का समय लगेगा।''

आरके सिंह, सीईओ, यमुना विकास प्राधिकरण, ''लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिकतर जमीन खरीदी जा चुकी है। बची जमीन भी जल्द खरीद ली जाएगी। इसके लिए किसानों से वार्ता की जा रही है। अन्य विकल्पों भी विचार हो रहा है।''

यूपी कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे की योजना को दी मंजूरी

बता दें कि, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में 17,542.06 करोड़ रुपये की लागत के करीब 322 किलोमीटर लंबे चार लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को 27 अक्टूबर को मंजूरी दी। राज्य सरकार इनका पूरा खर्च वहन करेगी और इन्हें तीन साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चार परियोजनाओं में करीब 90.90 किलोमीटर लंबा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है, जिसे दो पैकेज में बनाया जाएगा। इनके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 50.94 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे, करीब 106 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और करीब 74 किलोमीटर लंबा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को भी दो-दो पैकेज में विकसित किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में कामाख्या डेवलपर्स का दीपावली मिलन समारोह, बेस्ट चैनल पार्टनर्स को किया सम्मानित

अनप्लग इंडिया

ग्रेटर नोएडा। कामाख्या डेवलपर्स की ओर से ग्रेटर नोएडा स्थित रेड कार्पेट में भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजनीतिक, सामाजिक और रियल एस्टेट जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, आशीष भाटी, अन्नू पंडित, एडवोकेट अविनाश शर्मा, आयुष त्यागी ककड़ा, रक्षित गौतम और आशीष वत्स सहित कई अतिथि शामिल हुए। समारोह की शुरुआत भगवान श्री गणेश की वंदना और पूजा-अर्चना के साथ हुई। इसके बाद कामाख्या डेवलपर्स के निदेशकों देव शर्मा, प्रशांत शर्मा, रविंद्र नागर, अतुल चौहान और कुणाल शर्मा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

बेस्ट चैनल पार्टनर्स को किया सम्मानित



कार्यक्रम के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और बेस्ट चैनल पार्टनर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कंपनी से जुड़े चैनल पार्टनर्स और रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों ने समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर रियल एस्टेट क्षेत्र के इंफ्लुएंसर्स अमनदीप सिंह और अनुभव मोहन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

संगीत और मनोरंजन के बीच मनाया दीपावली का उत्सव

दीपावली मिलन समारोह में संगीत, मनोरंजन और सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और आपसी मेलजोल के साथ उत्सव मनाया।

कामाख्या डेवलपर्स के निदेशकों ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, चैनल पार्टनर्स और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ सहयोगियों के योगदान को सम्मान देने और भविष्य में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

समारोह का समापन उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ।

नोएडा में एनकाउंटर! शातिर बदमाश को पुलिस ने मारी गोली; 2 गिरफ्तार



अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा में पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। यहां के फेस-2 थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भंगेल गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर के बाद दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन और आकाश के रूप में हुई है।

इस मामले पर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि, पूछताछ में दोनों ने लूटपाट, चोरी और हत्या के प्रयास की कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बताया कि अमन के खिलाफ पूर्व में लूटपाट, चोरी और हत्या के प्रयास समेत 13 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस को देख भागे थे बदमाश

पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर पुलिस भंगेल गांव के पास अवरोधक लगाकर संदिग्धों की जांच कर रही थी और इसी दौरान बाइक सवार दो युवक आते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली अमन के पैर में लगी, जबकि उसका साथी आकाश मौके से फरार हो गया हालांकि, पुलिस ने पीछा कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे और अलग-अलग जगहों से लूटे गए छह मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की।

त्योहारों पर नोएडा में 24 घंटे मिलेंगी बसें, 305 बसें लगाएंगी 900 अतिरिक्त फेरे

अनप्लग इंडिया

नोएडा। दीपावली, भाईदूज और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो ने विशेष बस संचालन की तैयारी की है। दोनों डिपो की 305 बसें 6 से 17 नवंबर तक 900 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रात में भी बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

परिवहन निगम के आदेश के अनुसार, दीपावली 8 नवंबर और छठ पर्व 15 नवंबर को है। त्योहारों के दौरान बसों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 दिनों तक अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी।

दोनों डिपो की 305 बसें तैयार

क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार



सिंह ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो की सभी 305 बसों को दुरुस्त करा लिया गया है। 6 से 17 नवंबर तक यात्रियों को 24 घंटे बस सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जरूरत के अनुसार रात में भी बसें चलाई जाएंगी, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।

इन शहरों के लिए मिलेंगी बसें

नोएडा डिपो से कई प्रमुख शहरों के लिए बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इनमें बुलंदशहर, हरिद्वार, कोटद्वार, बिजनौर, मथुरा, आगरा, देहरादून, एटा और सहारनपुर शामिल हैं। नोएडा से लखनऊ के लिए भी बस सेवा मिलेगी।

वहीं, अन्य लंबी दूरी के शहरों के लिए यात्रियों को दिल्ली और गाजियाबाद के बस अड्डों से बस पकड़नी होगी।

ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को 4,800 रुपये तक प्रोत्साहन

त्योहारों के दौरान बिना छुट्टी लिए ड्यूटी करने वाले चालक और परिचालकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 11 दिन ड्यूटी करने और प्रतिदिन औसतन 300 किलोमीटर बस चलाने पर 4,400 रुपये मिलेंगे। 12 दिन ड्यूटी करने पर यह राशि बढ़कर 4,800 रुपये हो जाएगी।

ई-बस चलाने वाले नियमित और संविदा चालकों को 11 दिन में 3,300 किलोमीटर बस चलाने पर 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

कार्यशाला कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

बसों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़े कार्यशाला कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि तय की गई है। उन्हें 11 दिन ड्यूटी करने पर 2,100 रुपये और 12 दिन ड्यूटी करने पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे।

परिवहन निगम की इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालना और बस सेवाओं को सुचारु बनाए रखना है।

नोएडा के उद्यमियों को बड़ी राहत, यूनिफाइड रेगुलेशन-2025 में कई संशोधनों को मंजूरी

अनप्लग इंडिया

नोएडा। नोएडा के औद्योगिक कारोबारियों और उद्यमियों को राहत देने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने यूनिफाइड रेगुलेशन-2025 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने इस फैसले के लिए प्राधिकरण का आभार जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने 3 नवंबर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर इन संशोधनों को उद्यमियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। एसोसिएशन के पत्र के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक में यूनिफाइड रेगुलेशन-2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन बदलावों में औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण शुल्क, भूखंडों पर निर्माण पूरा करने की समय-सीमा, शेयरधारिता में बदलाव की सूचना और पारिवारिक शेयर हस्तांतरण से जुड़े नियम शामिल हैं।

औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण पर शुल्क घटेगा

NEA के मुताबिक, कार्यशील औद्योगिक इकाइयों के हस्तांतरण पर लगने वाला शुल्क 10 प्रतिशत के बजाय 7 प्रतिशत किए जाने से कारोबारियों को राहत मिलेगी। इससे औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन और नए निवेशकों के प्रवेश की लागत कम होने की उम्मीद है।

निर्माण पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय

औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण कार्य पूरा करने और इकाई को कार्यशील बनाने के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त समय देने का भी उल्लेख पत्र में किया गया है। इससे उन उद्यमियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें निर्धारित समय में निर्माण और उत्पादन शुरू करने में कठिनाई हो रही थी।

शेयरधारिता में बदलाव पर विलंब शुल्क कम

एसोसिएशन के पत्र के अनुसार, कंपनी की शेयरधारिता में बदलाव होने पर निर्धारित समय में सूचना नहीं देने पर लगने वाले विलंब शुल्क को 500 रुपये प्रतिदिन से घटाकर 300 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौक अंडरपास का निर्माण पूरा, दिवाली से पहले खोलने की तैयारी

अनप्लग इंडिया।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौक (चार मूर्ति चौक) पर यातायात की परेशानी कम करने के लिए बनाया जा रहा अंडरपास अब लगभग तैयार हो गया है। करीब 92 करोड़ रुपये की लागत से बने इस छह लेन के अंडरपास का मुख्य निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब सड़क की मार्किंग, स्ट्रीट लाइट लगाने, दीवारों की पेंटिंग और अन्य फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की योजना इसे दीपावली से पहले वाहनों के लिए खोलने की है।

करीब 700 मीटर लंबे इस अंडरपास के शुरू होने से गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास की आवासीय सोसायटियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी



गौर चौक पर लगने वाले जाम से राहत मिल सकती है।

अंडरपास की दीवारों पर दिखेगी देश की पहचान

अंडरपास को आकर्षक बनाने के लिए इसकी दीवारों पर कई खास चित्र बनाए गए हैं। इनमें इंडिया गेट, कुतुब मीनार, भगवान बुद्ध और चंद्रयान की पेंटिंग शामिल हैं। परियोजना में जलभराव की समस्या से बचाव को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के जीएम एके सिंह के मुताबिक, अंडरपास को दीपावली पर शुरू करना प्राथमिकता है। इसके चालू होने से गौर चौक पर यातायात का दबाव कम होगा और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

60 करोड़ से शुरू हुई परियोजना पर खर्च हुए 92 करोड़

इस परियोजना की शुरुआत लगभग 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान विभिन्न कार्यों और उपयोगिता सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के कारण कुल लागत बढ़कर करीब 92 करोड़ रुपये हो गई।

अंडरपास के मुख्य हिस्से की लंबाई लगभग 160 मीटर है, जबकि पूरी परियोजना करीब 730 मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। छह लेन की सुविधा के साथ इसे इस तरह तैयार किया गया है कि गौर चौक से गुजरने वाले वाहनों को सुगम रास्ता मिल सके।

जुलाई 2024 में शुरू हुआ था निर्माण

अंडरपास का निर्माण जुलाई 2024 में शुरू किया गया था। शुरुआती योजना के अनुसार इसे लगभग 18 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन कई वजहों से काम तय समय से आगे बढ़ गया।

निर्माण के दौरान वायु प्रदूषण के चलते लागू लग्नक प्रतिबंध, बारिश, भूमिगत और अन्य उपयोगिता सेवाओं को शिफ्ट करने तथा रैंप निर्माण से जुड़े कार्यों के कारण परियोजना की रफ्तार प्रभावित हुई।

अब मुख्य निर्माण पूरा होने के बाद अंतिम चरण के काम किए जा रहे हैं। यदि शेष कार्य निर्धारित समय पर पूरे हो जाते हैं तो दीपावली से पहले अंडरपास को आम लोगों के लिए खोलने का रास्ता साफ हो सकता है।

संपादकीय

चीन से बढ़ते व्यापार असंतुलन की चुनौती



हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इस समय चीन के साथ तेजी से बढ़ते व्यापार घाटे की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। सीतारमण ने कहा कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015-16 के 52.5 अरब डॉलर से दो गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 112 अरब डालर हो गया है। यद्यपि चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु चीन से भारत आने वाले आयात का विशाल परिमाण व्यापार घाटे की खाई को और अधिक गहरा बना रहा है। ऐसे में हमें हरसंभव तरीके से चीन से कारोबार में आ रही अड़चनें दूर करते हुए चीन को निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढना होगा। उल्लेखनीय है कि चीन के साथ लगातार बढ़ते हुए व्यापारिक असंतुलन के पीछे कई संरचनात्मक, रणनीतिक और नीतिगत कारक जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण चीन द्वारा अपनाई जाने वाली अप्रत्यक्ष और गैर-शुल्क बाधाएं (नॉन टैरिफ बैरियर्स) हैं। वित्त मंत्री के अनुसार चीनी प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले अत्यधिक जटिल तकनीकी, कड़े स्वास्थ्य और गुणवत्ता संबंधी सूक्ष्म मानक भारतीय वस्तुओं के चीनी बाजार में प्रवेश के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। भारत बीते एक दशक से भी अधिक समय से अपनी विश्वस्तरीय जेनेरिक दवाओं, प्रसंस्कृत मांस और विविध कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार में न्यायसंगत और पारदर्शी पहुंच की मांग करता रहा है। इसके विपरीत चीन अपने घरेलू उद्योगों और बाजार को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे जटिल नियामक नियम लागू करता है जिनके चलते भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी मूल्य और उच्च गुणवत्ता होने के बावजूद वहां अपनी पैठ नहीं बना पाते। इसके अतिरिक्त चीनी युआन की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव भी भारतीय मुद्रा रुपए पर लगातार दबाव बढ़ाते हैं, जिससे व्यापार घाटे को पाटने के लिए भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का निरंतर इस्तेमाल करना पड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान की चीनी कच्चे माल और घटकों पर बनी भारी निर्भरता है। यद्यपि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में तेजी से विस्तृत हुआ है, लेकिन इसका औद्योगिक बुनियादी ढांचा अब भी काफी हद तक चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, औषधीय कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और भारी औद्योगिक मशीनरी चीन से आने वाले आयात पर पूरी तरह टिके हुए हैं। इस संरचनात्मक निर्भरता का सीधा परिणाम यह निकलता है कि जैसे-जैसे भारत के भीतर औद्योगिक उत्पादन, असेंबलिंग और विनिर्माण गतिविधियां बढ़ती हैं,

साइबर हमले की नई चाल, परमाणु हमले का फर्जी अलार्म



महेन्द्र तिवारी
साहित्यकार एवं लेखक
पूर्व वायुसैनिक, नई दिल्ली

युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। अब यह लोगों के मोबाइल फोन, सरकारी सूचनाओं और उनके मन में पैदा होने वाले भय तक पहुँच गया है। यूक्रेन और रूस में हाल ही में हुई घटनाओं ने इस सच्चाई को एक बार फिर उजागर किया है। दोनों देशों के नागरिकों को सरकारी आपातकालीन चेतावनी अनुप्रयोगों के माध्यम से परमाणु हमले, विकिरण के खतरे और रासायनिक हमले से संबंधित झूठे संदेश भेजे गए। कुछ ही घंटों के अंतराल पर हुई इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि यदि नागरिकों को सुरक्षित रखने वाली व्यवस्था ही गलत सूचना फैलाने लगे, तो संकट के समय वे किस पर भरोसा करेंगे? एक नवंबर की रात यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक भय पैदा करने वाली सूचनाएँ आने लगीं। सामान्य परिस्थितियों में इन सूचनाओं का उद्देश्य लोगों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से आगाह करना तथा सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने में सहायता देना है। लेकिन उस रात चेतावनियों का स्वरूप ही बदल गया। लोगों को बताया गया कि कीव में विकिरण का खतरा है, रासायनिक हमला हो सकता है और कुछ स्थानों पर सड़क पर लड़ाई चल रही है। एक संदेश में पूरे यूक्रेन में परमाणु खतरे की चेतावनी दी गई। सबसे विचित्र संदेश रूसी भाषा में था। उसमें कहा गया कि परमाणु खतरा आने वाला है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस की ओर से ओरेश्निक मिसाइल आ रही है। ओरेश्निक रूस की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मानी जाती है। युद्ध के वातावरण में इस तरह का संदेश किसी भी सामान्य नागरिक को भयभीत कर सकता था। संदेशों में भाषागत अशुद्धियाँ भी थीं। कहीं अंग्रेजी और रूसी भाषा का मिश्रण था, तो कहीं यूक्रेनी भाषा के साथ दूसरी भाषाओं के शब्द जोड़े गए थे। इन असामान्य बातों ने संदेशों की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा किया। यूक्रेन की वायुसेना ने तत्काल लोगों को सावधान किया। उसने स्पष्ट किया कि विकिरण का कोई खतरा नहीं है और नागरिक शांत रहें तथा आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। अधिकारियों ने चेतावनी अनुप्रयोग की सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद कर दीं। बाद में उसे बहाल करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास किए गए। राहत की बात यह थी कि देश की दूसरी सार्वजनिक चेतावनी व्यवस्थाएँ और हवाई हमलों के संकेत देने वाले सायरन काम कर रहे थे। इस कारण झूठे संदेशों को वास्तविक हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना गया।

इस घटना के कुछ घंटे बाद रूस में भी लगभग ऐसा ही मामला सामने आया। दो नवंबर की सुबह रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के मोबाइल अनुप्रयोग पर साइबर हमला हुआ। इसके माध्यम से कई क्षेत्रों के लोगों को परमाणु आयुध छोड़े जाने की झूठी सूचना भेजी गई। संदेश में दावा किया गया कि रूस के सभी क्षेत्रों को परमाणु खतरा है। लोगों को खाद्य सामग्री जमा करने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने जैसी बातें भी कही गईं। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुप्रयोग के माध्यम से गलत सूचनाएँ प्रसारित की गई हैं। व्यवस्था को सामान्य बनाने के प्रयास शुरू किए गए। इन दोनों घटनाओं ने इसलिए भी ध्यान खींचा, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा है। ऐसे वातावरण में नागरिक हर दिन हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन से संबंधित समाचार सुनते हैं। यूक्रेन के अनेक शहरों में लोग वास्तविक चेतावनियाँ मिलने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं। ऐसे में यदि उसी माध्यम से परमाणु हमले या रासायनिक खतरे का झूठा संदेश आए, तो लोगों के लिए सही और गलत सूचना में अंतर करना कठिन हो सकता है। रूस में भी ऐसी चेतावनी से लोगों में घबराहट फैलने की आशंका स्वाभाविक है। इन साइबर हमलों के पीछे कौन था, इसका स्पष्ट उत्तर अभी सामने नहीं आया है। यूक्रेन के मामले में हिटकोर नामक समूह का उल्लेख किया गया। कुछ माध्यमों ने दावा किया कि इस समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। रूस में एटेश नामक यूक्रेन समर्थक समूह ने अपने माध्यमों पर हमले से संबंधित चित्र साझा किए। दूसरी ओर, कुछ रिपोर्टों में डीसी8044 नामक समूह का भी उल्लेख हुआ। अलग-अलग दावों के बावजूद यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दोनों हमले किसने किए या उनके पीछे कोई साझा योजना थी। दोनों घटनाओं का समय निकट होना अपने आप में उनके बीच संबंध का प्रमाण नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या इन हमलों को किसी देश की सरकार ने निर्देशित किया था? अभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। युद्ध के दौरान अनेक ऐसे समूह सक्रिय हो जाते हैं जो किसी पक्ष के समर्थन में स्वयं को साइबर योद्धा बताते हैं। कुछ समूह राजनीतिक विचारधारा के कारण सरकारी प्रणालियों को निशाना बनाते हैं, जबकि कुछ प्रसिद्धि पाने या विरोधी देश को अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियाँ करते हैं। जब तक ठोस प्रमाण सामने नहीं आते, तब तक किसी सरकार या संगठन को दोषी ठहराने से बचना चाहिए। इस घटना का सबसे गंभीर पहलू तकनीकी नुकसान से अधिक नागरिकों के विश्वास से जुड़ा है। आपातकालीन चेतावनी व्यवस्था का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में लोगों की मदद करना है। यदि इस व्यवस्था से बार-बार गलत संदेश आने लगें, तो नागरिक वास्तविक चेतावनी को भी संदेह की दृष्टि से देखने लग सकते हैं। इसे विश्वास का संकट कहा जा सकता है। वास्तविक हमले के समय कुछ मिनटों की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए चेतावनी प्रणाली की विश्वसनीयता किसी भी देश की नागरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घटना यह भी बताती है कि डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित रखना केवल तकनीकी विशेषज्ञों का काम नहीं है। सरकारों को अनुप्रयोगों की सुरक्षा जाँच नियमित रूप से करानी चाहिए। प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुँच रखने वाले खातों की कड़ी सुरक्षा, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, संदेश भेजने की अनुमति का सीमित उपयोग और किसी भी असामान्य सूचना की तत्काल जाँच आवश्यक है। यदि किसी अनुप्रयोग से परमाणु खतरे जैसी सूचना भेजी जाती है, तो उसे दूसरी स्वतंत्र व्यवस्था से सत्यापित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इससे एक माध्यम के प्रभावित होने पर पूरी चेतावनी व्यवस्था के विफल होने का खतरा कम किया जा सकता है। नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी भयावह संदेश को बिना जाँच के दूसरों तक पहुँचाना स्थिति को और गंभीर बना सकता है। ऐसी सूचना मिलने पर संबंधित सरकारी विभाग, स्थानीय प्रशासन और विश्वसनीय समाचार माध्यमों से उसकी पुष्टि करनी चाहिए। केवल किसी मोबाइल संदेश के आधार पर घबराकर घर छोड़ देना, भीड़ में शामिल होना या आवश्यक वस्तुओं की अनावश्यक खरीदारी करना नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही, वास्तविक खतरे की आशंका होने पर आधिकारिक निर्देशों की अनदेखी करना भी उचित नहीं है। सही रास्ता है कि सूचना की पुष्टि की जाए और अधिकृत चेतावनियों का पालन किया जाए। इस बार राहत की बात यह रही कि दोनों देशों की मुख्य सार्वजनिक चेतावनी व्यवस्थाएँ प्रभावित नहीं हुईं। यूक्रेन में सायरन और दूसरे माध्यम काम करते रहे, जबकि रूस ने भी अपने मोबाइल अनुप्रयोग को मुख्य चेतावनी व्यवस्था से अलग बताया। इससे तत्काल नुकसान की आशंका कम हुई। कुछ लोगों ने इन विचित्र संदेशों को हास्यास्पद मानकर उनका मजाक भी बनाया, लेकिन इससे घटना की गंभीरता कम नहीं हो जाती। परमाणु युद्ध और रासायनिक हमले जैसे विषयों पर झूठी सूचना फैलाना किसी भी परिस्थिति में सामान्य शरारत नहीं माना जा सकता। आधुनिक युद्ध में विजय केवल हथियारों की संख्या या सैन्य शक्ति से तय नहीं होती। सूचना पर नियंत्रण, तकनीकी प्रणालियों की सुरक्षा और नागरिकों के मनोबल को प्रभावित करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर हमलावर बिना सीमा पार किए, बिना किसी मिसाइल को दागे और बिना किसी सैनिक को मैदान में उतारे लाखों लोगों के मन में भय पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यूक्रेन और रूस में हुई ये घटनाएँ पूरी दुनिया के लिए चेतावनी हैं। आज जिन देशों के बीच युद्ध चल रहा है, कल ऐसी ही कोशिशें किसी अन्य देश की आपदा चेतावनी, स्वास्थ्य सेवा या परिवहन व्यवस्था को निशाना बना सकती हैं। भारत जैसे विशाल और तकनीकी रूप से तेजी से आगे बढ़ते देश के लिए भी यह सीख महत्वपूर्ण है। नागरिकों को समय पर सही सूचना देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस सूचना के माध्यम को सुरक्षित रखना है। संकट की घड़ी में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। यदि तकनीक पर किया गया हमला इस भरोसे को तोड़ने लगे, तो उसका असर किसी एक अनुप्रयोग तक सीमित नहीं रहेगा। वह समाज की सुरक्षा, शांति और सामूहिक विवेक को भी प्रभावित करेगा।

'वोट चोरी' से लोकतंत्र पर हमला: इंडिया ब्लॉक की दिल्ली महारैली का संदेश

-सचिन कुमार गौतम

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को हुई इंडिया ब्लॉक की महारैली केवल एक विपक्षी प्रदर्शन नहीं थी; वह लोकतंत्र, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर उठी एक बड़ी राजनीतिक आवाज थी। रैली का केंद्रीय संदेश स्पष्ट था–विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढुक्र) को रोका जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और 'वोट चोरी' के आरोपों पर जवाबदेही तय हो।

एक मंच, कई आवाजें

रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों और अन्य विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आए। अलग-अलग नेताओं की भाषा अलग थी, पर उनका निचोड़ एक था: मतदाता सूचियों में कथित बड़े पैमाने पर नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया पर सवालों के बीच जनता के वोट का अधिकार खतरे में है।

'मोदी हटाओ, देश बचाओ,' 'वोट चोर, गद्दी छोड़,' और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' जैसे नारों ने मैदान की हवा भर दी। ये नारे केवल भावुकता का इज़हार नहीं थे; ये उस राजनीतिक संदेश का हिस्सा थे जिसे इंडिया ब्लॉक 2027 के चुनावों से पहले राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह आम चोरी नहीं, बल्कि हर नागरिक की आवाज और वोट की चोरी है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कानूनी कार्रवाई की मांग की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भी भविष्य में कानूनी कार्रवाई की बात कही।

रैली का राजनीतिक संदेश

इस रैली की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता थी। इसमें केवल दलीय कार्यकर्ता नहीं थे; किसान, मजदूर, छात्र, घरेलू कामगार, महिलाएं, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इससे विपक्ष की कोशिश साफ दिखी कि वह स्ढुक्र को केवल कानूनी-तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि आम नागरिक के राजनीतिक अधिकार का सवाल बनाना चाहता है।

विपक्ष का तर्क था कि जब मतदाता सूची से नाम हटते हैं, तो यह केवल कागजी प्रक्रिया नहीं रह जाती। यह उस नागरिक की राजनीतिक पहचान पर असर डालता है, जिसका नाम सूची से गायब हो जाता है। इसीलिए रैली में स्ढुक्र को रद्द करने और चुनाव आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग केंद्र में रखी गई।

भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया और रैली की भीड़ के दावों पर सवाल उठाया। लेकिन विपक्ष के लिए असली संदेश भीड़ के आंकड़े से अधिक महत्वपूर्ण था–यह कि विभिन्न दल, सामाजिक संगठन और छात्र संगठन एक मुद्दे पर साथ खड़े हो सकते हैं।

मौसम, प्रबंधन और जुनून

रैली से पहले दिल्ली में बारिश से मैदान में कीचड़ और पानी भर गया था। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने मैदान तैयार करने और लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। विपक्ष के अनुसार, यह भीड़ दिखाती है कि लोग पुलिस की सख्ती, कोर्ट-कचहरी के चक्कर और प्रताड़ना के डर के बावजूद अपनी आवाज उठाने के लिए आए।

राहुल गांधी ने शनिवार रात लोगों से अपील की थी कि वे रैली में आकर थोड़ी खरीदारी करें, ताकि दीपावली के मौके पर दिल्ली के व्यापारियों को फायदा हो। इस अपील के पीछे एक राजनीतिक संदेश भी था–विपक्ष ने यह दिखाना चाहा कि वह जन-आंदोलन को व्यापार और आम जीवन के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके समर्थन में प्रस्तुत कर रहा है।

1984 का मुद्दा और कांग्रेस का जवाब

रैली से पहले भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने पंजाब में इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। यह कोशिश इसलिए की गई कि रैली से पहले विपक्ष का ध्यान 'वोट चोरी' से हटाया जा सके।

लेकिन इतिहास में कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर माफी और जिम्मेदारी के बयान भी दर्ज हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा में कहा था कि वे सिख समुदाय और पूरे राष्ट्र से माफी मांगते हैं, क्योंकि 1984 में जो हुआ वह संविधान में निहित राष्ट्रवाद की अवधारणा के खिलाफ था।

राहुल गांधी ने भी पहले कई मौकों पर कांग्रेस की उस दौर की गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। इसलिए विपक्ष का तर्क है कि 1984 को राजनीतिक हथियार बनाकर रैली के असली मुद्दे–स्ढुक्र और चुनाव आयोग–से ध्यान हटाने की कोशिश नाकाम हुई।

'मॉक पार्लियामेंट' का प्रतीक

रैली से एक दिन पहले, शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास के बगीचे में एक प्रतीकात्मक 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित हुई। इसमें विपक्षी नेता और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि सांसदों की तरह बैठे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव पारित किया।

टेनिस कोर्ट की शपथ की तुलना

राहुल गांधी ने इस आयोजन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से पहले की घटना से की। 1789 में जब लुई सोलहवें ने आम जनता के प्रतिनिधियों के लिए संसद के दरवाजे बंद कर दिए, तो प्रतिनिधियों ने टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर शपथ ली थी कि वे तब तक भंग नहीं होंगे जब तक फ्रांस में संवैधानिक व्यवस्था नहीं आ जाती।

यह तुलना भावुक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थी। इसका अर्थ यह था कि जब संस्थागत रास्ते बंद हो जाएं, तो लोकतंत्र के हिमायती बाहर आकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। विपक्ष यह संदेश देना चाहता था कि उसका संघर्ष किसी एक नेता या दल के लिए नहीं,

मोबाइल की दुनिया और बचपन का बिगड़ता व्यवहार

– डॉ. प्रियंका सौरभ

पंचकूला के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा छह साल की बच्ची के साथ कथित क्रूर व्यवहार की खबर ने समाज को झकझोर दिया है। समाचार में सामने आए घटनाक्रम और विद्यालय परिसर में हुई हिंसा के विवरण ने बच्चों की सुरक्षा, उनके व्यवहार और हमारी परवरिश को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर बचपन में ऐसी हिंसक प्रवृत्तियाँ कैसे जन्म ले रही हैं? क्या बच्चों के भीतर संवेदनशीलता और सहानुभूति कम हो रही है? क्या मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक सामग्री और बदलते पारिवारिक वातावरण का उनके व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? इन सवालों से बचना अब संभव नहीं है।

किसी एक घटना के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि बच्चों में बढ़ती हिंसा का कारण केवल मोबाइल फोन है। प्रत्येक घटना के पीछे व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, पारिवारिक वातावरण, साथियों का प्रभाव, मानसिक स्थिति और सामाजिक परिवेश जैसे अनेक कारक हो सकते हैं। फिर भी यह सच है कि बच्चों के हाथों में पहुँच चुकी डिजिटल दुनिया ने माता-पिता की जिम्मेदारियों को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। अब बच्चों की निगरानी केवल स्कूल से लौटने के बाद उनके व्यवहार तक सीमित नहीं रह सकती। यह जानना भी आवश्यक है कि वे मोबाइल पर क्या देखते हैं, किन लोगों से बातचीत करते हैं, कौन-से खेल खेलते हैं और इंटरनेट से किस प्रकार के विचार ग्रहण कर रहे हैं।

आज स्मार्टफोन बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, शैक्षिक वीडियो और ज्ञानवर्धक सामग्री के माध्यम से तकनीक ने सीखने के नए अवसर खोले हैं। लेकिन इसी माध्यम पर हिंसक दृश्य, अपमानजनक भाषा, खतरनाक चुनौतियाँ और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। समस्या तकनीक के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग, अनुचित सामग्री तक पहुँच और उसके प्रभावों को समझने की कमी में है। बच्चे कई बार मनोरंजन के नाम पर ऐसी सामग्री देखते हैं, जिसके परिणामों को समझने के लिए वे मानसिक और भावनात्मक रूप से पर्याप्त परिपक्व नहीं होते।

बचपन अनुकरण की अवस्था है। बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर भाषा, व्यवहार और प्रतिक्रिया करना सीखते हैं। वे माता-पिता की बातचीत, परिवार के सदस्यों के आचरण, मित्रों के व्यवहार और डिजिटल माध्यमों पर दिखाई देने वाली गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार-बार हिंसा, अपमान, बदले और आक्रामकता को सामान्य रूप में प्रस्तुत करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, तो उसके व्यवहार पर उनका प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि हर बच्चा ऐसी सामग्री देखकर हिंसक नहीं बनता, लेकिन उम्र के अनुरूप सामग्री चुनना और उसके प्रभावों पर बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है।

इस संदर्भ में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर व्यस्तता के कारण बच्चों को शांत रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। खाना खिलाने से लेकर उन्हें व्यस्त रखने तक, स्क्रीन एक आसान उपाय बन गई है। धीरे-धीरे यह आदत बच्चों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है और अभिभावकों का ध्यान इस बात से हट जाता है कि बच्चा वास्तव में क्या देख रहा है। बच्चे का मोबाइल पर चुपचाप लगे रहना उसकी सुरक्षा या स्वस्थ विकास का प्रमाण नहीं है। डिजिटल दुनिया में उसकी गतिविधियों की जानकारी रखना, उम्र के अनुरूप सीमाएँ निर्धारित करना और उसके साथ नियमित संवाद बनाए रखना आवश्यक है।

बच्चों पर नजर रखने का अर्थ उन पर हर समय संदेह करना या उनकी निजता को पूरी तरह समाप्त कर देना नहीं है। इसका अर्थ है उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहना और ऐसा विश्वासपूर्ण वातावरण बनाना, जिसमें वे अपनी परेशानी, जिज्ञासा और गलतियों के बारे में खुलकर बात कर सकें। माता-पिता को बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कौन-से खेल खेलते हैं, इंटरनेट पर क्या नया देखते हैं और किसी वीडियो या घटना के बारे में उनकी क्या समझ है। यदि बच्चा किसी हिंसक दृश्य को देखकर उत्साहित होता है, किसी को चोट पहुँचाने की बात करता है या उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आता है, तो उसे केवल डाँटकर चुप कराने के बजाय कारण समझने का प्रयास करना चाहिए।

विद्यालयों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं है। विद्यालय बच्चों को संवेदनशील, जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने का भी माध्यम हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार में आने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में परामर्श व्यवस्था, भावनात्मक शिक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और दूसरों की गरिमा का सम्मान करने से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बच्चों के बीच मारपीट, धमकी, अपमान या किसी कमजोर विद्यार्थी को निशाना बनाने की घटनाओं को सामान्य शरारत समझकर टालना भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।

साथ ही, किसी बच्चे द्वारा गंभीर गलती किए जाने पर उसके व्यवहार की जवाबदेही तय करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि जाँच और कार्रवाई तथ्यों के आधार पर हो। बच्चों को अपराधी घोषित करने की जल्दबाजी, सार्वजनिक अपमान या सोशल मीडिया पर उनकी पहचान उजागर करना उचित नहीं है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में हिंसा, असामान्य आक्रामकता या भावनात्मक संकट के संकेत दिखाई दें, तो अभिभावकों और विद्यालयों को योग्य बाल मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

डिजिटल मंचों और सरकार की भूमिका पर भी विचार करना होगा। बच्चों के लिए अनुचित सामग्री तक पहुँच रोकने, अभिभावकीय नियंत्रण के साधनों को सरल बनाने और आयु के अनुरूप डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इंटरनेट कंपनियों को भी बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन किसी तकनीकी सुविधा पर पूरी तरह निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना सीखना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज सही, सुरक्षित या अनुकरण करने योग्य नहीं होती।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को केवल नियमों से नहीं, उदाहरणों से भी सिखाया जाता है। यदि घर में गुस्से के समय अपशब्दों का प्रयोग होता है, विवादों का समाधान मारपीट से किया जाता है और दूसरों के प्रति अपमानजनक व्यवहार सामान्य माना जाता है, तो बच्चों से पूर्णतः विपरीत आचरण की अपेक्षा करना कठिन होगा। परिवार में संवाद, धैर्य, सहानुभूति और सम्मान का वातावरण बनाना होगा। बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें खेलकूद, पुस्तक-पठन, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल के अवसर देना भी जरूरी है। पंचकूला की घटना से उपजे सवाल केवल एक विद्यालय या एक परिवार तक सीमित नहीं हैं। वे पूरे समाज के सामने एक चेतावनी की तरह खड़े हैं। हमें बच्चों को तकनीक से दूर रखने की बजाय उसका सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सिखाना होगा। मोबाइल पर वे क्या देख रहे हैं, यह जानने के साथ-साथ यह भी समझना होगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं वे अकेलेपन, तनाव, उपेक्षा या किसी अनकही परेशानी से तो नहीं जूझ रहे?

बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से पहले उन्हें विवेक देना, स्वतंत्रता देने से पहले जिम्मेदारी सिखाना और अनुशासन के साथ स्नेह देना आज समय की मांग है। बचपन को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी केवल माता-पिता या शिक्षकों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है।

दस दिन में चार चुनाव : तानाशाही को आखिरकार मिल रहा है जवाब

नित्य चक्रवर्ती

स्टूडेंट स्ट्रीट पिछले 14 सालों में वुसिक शासन के तानाशाही रवैए को खत्म करके देश को असली लोकतंत्र में बदलने के लिए 11सूत्री योजना पर काम कर रहा है। नए युवा नेता कह रहे हैं कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थानों के काम करने को पारदर्शी तरीके से पक्का करेंगे। जैसा कि एक लीडर ने समझाया कि पहला काम देश का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषमुक्तिकरण होना चाहिए। इस साल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सिर्फ दस दिनों में, चार राष्ट्रीय चुनाव तय थे। इनमें से, ब्राज़ील और सर्बिया में 25 अक्टूबर को और इज़राइल में 27 अक्टूबर को चुनाव हुए। सिर्फ 3 नवंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच कड़वाहट से भरा चुनाव अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसमें सभी जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट पार्टी को बढ़त मिली है। अब तक आये तीनों चुनाव नतीजों में तानाशाही के ख़िलाफ़ एक पक्का संदेश है। ब्राज़ील में, रविवार रात को चुनाव के घोषित अंतिम नतीजे, लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अमेरिका का उपनिवेश बनाने के इरादे वाले घोर दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ़्लावियो बोल्सोनारो के कदमों के ख़िलाफ़ ब्राज़ील के लोगों की प्रभुसत्ता की पुष्टि थे। ब्राज़ील के मतदाताओं ने उनकी योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और वाम गठबंधन के उम्मीदवार लूला को अगले चार साल के लिए सत्ता सौंप दी, जिससे वे चौथी बार राष्ट्रपति बन गए।

फ्लेवियो बोल्सोनारो ने अब अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ अमेरिका में शरण ले ली है। उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन जेल में बंद उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से फ़र्क यह था कि सीनियर बोल्सोनारो 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में अपनी हार के बाद भी ब्राज़ील में ही रहे और विद्रोह करने की कोशिश की। वे नाकाम रहे और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें देशद्रोह के लिए 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई।

फ्लेवियो बोल्सोनारो के अमेरिका में बसने का तुरंत नतीजा ब्राज़ील के अति दक्षिणपंथी शाखा में निराशा है। अब कोई भी असरदार अति दक्षिणपंथी नेता नहीं है जो राष्ट्रपति लूला का मुकाबला कर सके। अति दक्षिणपंथी शाखा ने पहले चक्र में अच्छा प्रदर्शन किया और हाउस ऑफ़ डेप्युटीज़ में बहुमत और सीनेट में दो-तिहाई सीटें हासिल की। दोनों सदनों में बोल्सोनारो परिवार के बहुत सारे चुने हुए सदस्य हैं। लेकिन ब्राज़ील में अति दक्षिणपंथी शाखा का नेतृत्व संभालने के लिए किसी को भी काबिल नहीं माना जा रहा है। ब्राज़ील में सत्तारूढ़ गठबंधन अब जोश में है और काफी सक्रियता दिखा रहा है क्योंकि दो दूसरी दक्षिणपंथी पार्टियां, जिन्होंने चुनावों में बोल्सोनारो को समर्थन दिया था, फ्लेवियो के अमेरिका से ब्राजील की राजनीति चलाने के फैसले से दूर

संक्षिप्त समाचार

गृहमंत्री अमित शाह के करनाल दौरे से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह : कपूर

अनप्लग इंडिया

करनाल। लोकतंत्र बचाओ,अराजकता हटाओ अभियान के अंतर्गत 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करनाल आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं एवं आमजन में खासा उत्साह का वातावरण बन गया है।भाजपा के जिला प्रवक्ता शिव नाथ कपूर के अनुसार भाजपा की प्रदेश अध्यक्षा डाक्टर अर्चना गुप्ता सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं भाजपा नेता गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यषस्थाओं का जायाजा कर रहे हैं तथा अपेक्षित जनसमूह जुटाने के लिए समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रहे हैं वहीं जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जिले में मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठकें करके अमित शाह के इस कार्यक्रम में भीड जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां लगा रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था तथा व्यवस्थित कार्यक्रम के आयोजन के लिए उपायुक्त डॉ.आनंद एवं पुलिस उपाधीक्षक पूरी तरह प्रशासनिक ढांचे के साथ पूरी तरह सक्रिय हो गये हैं वहीं करनाल के विधायकजगमोहनआनंद, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी,असंध के विधायक योगेन्द्र राणा,घरौंडा के विधायक एवं विधानसभाध्यक्ष हरविंद्र कल्याण एवं इंद्री के राम कुमार कश्यप विधायक भी अपने-अपने विधानसभा में पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके आमजन को अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं।

जिला प्रवक्ता शिव नाथ कपूर के अनुसार प्रदेशाध्यक्षा डाक्टर अर्चना गुप्ता के साथ सत्य प्रकाश जवात्रा,जवाहर सैनी,ललित बत्रा,अमर पाल राणा,रामेश्वर दयाल चौहान तथा जिला प्रभारी जवाहर यादव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी कार्यकर्ताओं की निरंतर बैठकें ले रहे हैं तथा अमित शाह के कार्यक्रम को भव्यतापूर्ण बनाने के लिए हरसंभव प्रयास में जुटे हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह जनसमूह को संबोधित करने के उपरांत करीब 2 किलोमीटर की पदयात्रा भी करेंगे।इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी,केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद मनोहर लाल खट्टर भी मुख्य रुप से अमित शाह के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।

ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को रफ्तार देने पर सीएम नयाब सिंह सैनी का आभार : मंत्री राजेश नागर



अनप्लग इंडिया

चंडीगढ। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री एवं तिगांव के विधायक राजेश नागर ने ग्रेटर फरीदाबाद को एनआईटी फरीदाबाद से जोड़ने वाले लगभग 753 करोड़ रुपये की लागत के महत्वाकांक्षी एलिवेटेड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। राजेश नागर ने कहा कि यह परियोजना फरीदाबाद के विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। इससे ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी न केवल एनआईटी क्षेत्र से मजबूत होगी, बल्कि गुरुग्राम की ओर आवागमन भी पहले से अधिक सुगम और सुविधाजनक हो सकेगा। इस परियोजना का टेंडर 17 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिससे इसके धरातल पर उतरने का रास्ता साफ होगा। मंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की मांग उन्होंने विधायक रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाई थी। उनका उद्देश्य था कि तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर फरीदाबाद को शहर के पुराने हिस्सों और प्रमुख मार्गों से सीधे जोड़ा जाए, ताकि लोगों को जाम और लंबी दूरी की परेशानी से राहत मिल सके। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और सकारात्मक सोच से यह प्रयास साकार होने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सैनिक कॉलोनी मोड़ से ग्रेटर फरीदाबाद और अमृता अस्पताल तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर से बड़खल, अनखीर, मस्जिद चौक, प्याली-हार्डवेयर और बाटा चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा। परियोजना के तहत विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा के संतुलित विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह परियोजना आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाने के साथ-साथ औद्योगिक, व्यावसायिक और शहरी विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। उन्होंने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का पुनः धन्यवाद किया।

जनप्रतिनिधि सम्मेलन में उभरे विचार संविधान पखवाड़े के कार्यक्रमों का बनेंगे आधार : हरविन्द्र कल्याण

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण विचार और विषय उभरकर सामने आए हैं, वे बीज मंत्र के समान हैं। इन विचारों को व्यापक विमर्श का हिस्सा बनाने और जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संविधान पखवाड़े के तहत विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जाएगा। विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि जनप्रतिनिधि सम्मेलन वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के सम्मान, उनके अनुभवों से सीखने और नई पीढ़ी की ऊर्जा एवं सोच को दिशा देने का एक सार्थक मंच साबित हुआ। वरिष्ठ पूर्व विधायक हमारी सामाजिक और लोकतांत्रिक धरोहर हैं। उनका अनुभव, ज्ञान और सक्रियता आज भी समाज के लिए उपयोगी है। संविधान पखवाड़े के तहत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे आयोजन करने का उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी को वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के संघर्ष, अनुभव और सार्वजनिक जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा मिल सके। उनका व्यावहारिक अनुभव पुस्तकीय ज्ञान से कहीं अधिक व्यावहारिक सीख प्रदान करता है। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान पखवाड़े के आगामी कार्यक्रमों में संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों, संसदीय कार्यप्रणाली, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की योजना है। सम्मेलन में अनुभवी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से जिस प्रकार मार्गदर्शन किया है, उसे आगे भी संवाद और विमर्श के जरिए समाज तक पहुंचाया जाएगा। सम्मेलन के दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा करते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं, विकास यात्रा, जनसेवा और संवैधानिक दायित्वों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

पूर्व मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा : उन्होंने विधान सभा की ओर से आयोजित इस अभिनव पहल की सराहना की। 26 अगस्त 2016 को विधान सभा में जैन मुनि तरुण सागर के प्रवचनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है और हमें वरिष्ठ एवं अनुभवी लोगों के जीवन अनुभवों से सीखना चाहिए, जो प्रदेश की उन्नति का आधार भी है।

पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा : उन्होंने हरियाणा के गठन के शुरुआती दौर की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां थीं।

भगवंत मान ने बनाई धुरी से दूरी, पंजाब के लोगों ने दीवारों पर लिखी भाजपा की जीत की इबारत : नायब सिंह सैनी

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में सात एजेंडे रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने पत्रकार बंधुओं को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याण और विकास के कार्यों को निरंतर गति दे रही है।मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान पखवाड़े के तहत 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया एवं अतिरिक्त निदेशक कैप्टन मनीष लोहान भी उपस्थित थे। *मोदी सरकार के नेतृत्व में गरीब, युवा, महिला और किसान को मिल रही है मजबूती*

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास कार्य तीन गुना गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले केवल घोषणाएं और बातें



होती थीं, जबकि भ्रष्टाचार के कारण विकास के लिए आने वाला पैसा सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। आज योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है और आमजन को इसका लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची-बिना पर्ची के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। पहले युवाओं को नौकरी पाने के लिए पैसे और सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर योग्यता को प्राथमिकता दी है। सरकार ने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के खिलाड़ी देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है और प्रदेश में करीब 1 लाख 60 हजार मकान बनाकर जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य महिला, किसान, युवा और गरीब सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना है।

629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे की व्यवस्था तथा शेड निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है, ताकि गौवंश के रखरखाव और देखभाल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में गत दिवस प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग गौशालाओं के रखरखाव, चारे की व्यवस्था, शेड निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है और गौशालाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

पंजाब में भाजपा की सरकार बनने का दावा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा

पंजाब की राजनीति से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में अब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने का समय आ गया है। पंजाब की जनता ने दीवारों पर भाजपा की जीत की इबारत लिख दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में दोनों ही विफल रही हैं। कांग्रेस ने हर घर में रोजगार देने का वादा किया था, वहीं आम आदमी पार्टी ने 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। अब पांच साल का समय बीत चुका है, इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब के युवाओं को बताना चाहिए कि उसने कितने लोगों को वास्तव में रोजगार दिया है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आज पंजाब में कार्यक्रमों के दौरान रिबन काटने और लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन जनता अब उनके वादों और कामकाज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में पंजाब में सरकार बनेगी।

मुख्यमंत्री ने पंजाब में किसानों और महिलाओं से किए गए वादों को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने किसानों का शोषण किया है और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा करके उन्हें भी निराश किया है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने से पहले बड़े-बड़े वादे करने वाली आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद किसानों और महिलाओं के लिए वास्तव में क्या किया है।

पंजाब में राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने से रोकने और आयोजकों को धमकाने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को पंजाब में आने से रोका जा रहा है और कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर दबाव बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में सरकार की कार्यप्रणाली का एक चिंताजनक चेहरा सामने आ रहा है। पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हरियाणा में ऐसी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

मनीषा की उपलब्धि हरियाणा सहित पूरे देश के लिए गौरव का विषय : नायब सिंह सैनी

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मंगलवार को जींद जिले की अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं वर्ल्ड चैंपियन मनीषा भनवाला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कज़ाकिस्तान में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने पर मनीषा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीषा की यह ऐतिहासिक उपलब्धि हरियाणा सहित पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। उन्होंने मनीषा को भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और हरसंभव सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, कोच मनदीप सिंह भी मौजूद रहे। मनीषा भनवाला ने कजाकिस्तान में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला पहलवान के रूप में यह ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। मनीषा इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2025 में जॉर्डन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा, वर्ष 2026 में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। मनीषा की अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों का सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं है।



उन्होंने वर्ष 2022 की एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक, वर्ष 2023 में कांस्य पदक तथा वर्ष 2024 में पुनः कांस्य पदक जीतकर लगातार शानदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की बेटियां खेलों के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मनीषा भनवाला जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रदेश की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

दीपावली पर 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का चुनावी वादा पूरा करे हरियाणा सरकार : कुमारी सैलजा

अनप्लग इंडिया

सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि वह दीपावली के अवसर पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत कार्यरत लगभग 1.20 लाख कर्मचारियों को नियमित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करे। सांसद ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और उनके रोजगार को सुरक्षित करने का भरोसा दिलाया था। अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह अपना वादा कब पूरा करेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। महंगाई के इस दौर में सीमित वेतन और नौकरी की असुरक्षा के बीच परिवार का पालन-पोषण करना कठिन हो रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि दीपावली खुशियों और उम्मीदों का पर्व है। ऐसे में सरकार यदि नियमितीकरण की ठोस घोषणा करती है तो यह हजारों कर्मचारी परिवारों के लिए वास्तविक सौगात होगी। कर्मचारियों को बार-बार आश्वासन देने के बजाय सरकार को अब निर्णय लेना चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि नियमितीकरण की नीति संविधान, न्यायालयों के निर्णयों और सेवा नियमों के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। कर्मचारियों की सेवा अवधि, अनुभव और कार्य की प्रकृति को उचित महत्व मिले। सरकार कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करे।

सांसद ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार सुरक्षा की पक्षधर है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा सरकार इस दीपावली पर 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर अपना चुनावी वादा निभाएगी या उन्हें फिर इंतजार करना पड़ेगा?

उत्तराखंड में परिवर्तन का मन बना चुकी है जनता : कुमारी सैलजा

उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने बताया कि नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के नेतृत्व में आयोजित बैठक में उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर विफल रही है। सांसद ने कहा कि उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस जनहित, विकास और जवाबदेही के मुद्दों पर पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी।

गुड़गांव में लगातार धंस रही सड़कें, क्या रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं शासन-प्रशासन: पंकज डावर

अनप्लग इंडिया

गुड़गांव। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने कहा कि गुड़गांव में सड़कें धंसने का क्रम थम नहीं रहा है। बार-बाहर सड़कें धंस रही हैं। लगता है कि सरकार सड़कें धंसने का ही रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। यह भ्रष्टाचार की बड़ी बानगी है कि एक ही सड़क गुरुग्राम-सोहना हाइवे पर सातवीं बार धंस गई। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे-48 पर फ्लाईओवर पर दो साल से कंक्रीट गिरते-गिरते आरपास नजर आने लगा है, उसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। इन घटनाओं से साफ है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, मगर सरकार आंखें मुंदे बैठी है। पंकज डावर ने विशेष रूप से गुरुग्राम-सोहना हाइवे का जिक्र करते हुए कहा कि यह हाइवे भ्रष्टाचार की जीती-जागती मिसाल बन गया है। करोड़ों रुपये की लागत से बना यह हाइवे सातवीं बार धंस गया है। उन्होंने कहा कि एक ही हाइवे का एक ही हिस्सा सात बार धंस जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या हो सकता है। हर बार सरकार लीपापोती करती है, मिट्टी डालकर गड्ढा भर दिया जाता है, फिर कुछ महीनों बाद वही सड़क फिर धंस जाती है। जनता की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम-सोहना हाइवे से हजारों लोग रोजाना सोहना, नूंह और अलवर की तरफ आते-जाते हैं। जब से यह हाइवे बना है, तब से यह हादसों का हाइवे बन गया है। कभी सर्विस लेन धंस जाती है तो कभी मुख्य सड़क। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक से यह सड़क बनाई गई है जो हर बारिश में या बिना बारिश के ही बैठ जाती है। पंकज डावर ने कहा कि सड़कें धंसने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। अगर पहली बार सड़क धंसने पर ही ठेकेदार पर कार्रवाई होती, उसकी सिक्योरिटी जब्त होती और ब्लैकलिस्ट किया जाता, तो आज सातवीं बार यह नौबत नहीं आती। सरकार में बैठे लोगों की ठेकेदारों से मिलीभगत है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। डावर ने दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे-48 का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एनएच-48 पर बने फ्लाईओवरों की हालत भी खस्ता है। पिछले दो साल से इन फ्लाईओवरों से कंक्रीट के टुकड़े गिर रहे हैं। सरिये यानी आरपार तक नजर आने लगे हैं, लेकिन एनएचएआई और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जब कोई गाड़ी नीचे गिरते मलबे की चपेट में आएगी, तब सरकार जागेगी। उन्होंने कहा कि गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां की बुनियादी सुविधाएं ही सबसे ज्यादा बदहाल हैं। सड़कें धंस रही हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कूड़े के पहाड़ लगे हैं। यह कैसी स्मार्ट सिटी है। यह तो भ्रष्टाचार की स्मार्ट सिटी बन गई है। पंकज डावर ने मांग की कि गुरुग्राम-सोहना हाइवे के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो, जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को शामिल किया जाए। साथ ही जिस कंपनी ने यह हाइवे बनाया है, उसे ब्लैकलिस्ट कर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी और जनता को साथ लेकर हाइवे जाम करेगी।



● बार-बाहर सड़कें धंस रही हैं। लगता है कि सरकार सड़कें धंसने का ही रिकॉर्ड बनाना चाह रही है। यह भ्रष्टाचार की बड़ी बानगी है कि एक ही सड़क गुरुग्राम-सोहना हाइवे पर सातवीं बार धंस गई। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे-48 पर फ्लाईओवर पर दो साल से कंक्रीट गिरते-गिरते आरपास नजर आने लगा है, उसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। इन घटनाओं से साफ है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, मगर सरकार आंखें मुंदे बैठी है।

गुरुग्राम निगम के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश

अनप्लग इंडिया

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन, रखरखाव एवं हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत मेजर पेनल्टी कार्यवाही शुरू करने के लिए चार्जशीट जारी करने की सिफारिश की है। इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के आयुक्त व सचिव को पत्र भेजा गया है।

मामला नगर निगम की मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित छह माह के दो अनुबंधों के दौरान मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं से जुड़ा है। निगम द्वारा 20 मशीनों के लिए 26 सितंबर 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था, जबकि पांच मशीनों के लिए 12 अगस्त 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था। संबंधित अवधि में कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण इस कार्य के प्रभारी थे। निगमायुक्त द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त निगमायुक्त यश जलुका को सौंपी गई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को जांच की तथा 28 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में संबंधित कार्यकारी अभियंता और एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जांच रिपोर्ट में मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में पर्याप्त तकनीकी सत्यापन नहीं किए जाने, मशीनों एवं उनके कलपुर्जों की वास्तविक स्थिति का उचित लिखित रिकॉर्ड और प्रमाणन उपलब्ध नहीं होने तथा निगम की संपत्तियों की सुरक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी नहीं किए जाने जैसी कमियां सामने आईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व एजेंसी जे.के. कॉन्ट्रैक्टर से मशीनों की मरम्मत लागत की वसूली तथा अनुबंध के तहत निर्धारित पेनल्टी लगाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला।

जांच के दौरान नई एजेंसी राधा कृष्ण सोसाइटी लिमिटेड की जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। आरएफपी की शर्त संख्या 3.6 के अनुसार एजेंसी को बोली लगाने से पहले मशीनों का निरीक्षण करना तथा उन्हें जैसी हैं,

हरियाणा में चुनाव से पहले बने डबल वोटों का एसआईआर से किया जा रहा बचाव : दुष्यंत चौटाला

अनप्लग इंडिया

चंडीगढ़। मंगलवार को जननायक जनता पार्टी ने छह दिसंबर को महेंद्रगढ़ जिले में होने वाली स्थापना दिवस रैली की तैयारियां को आगे बढ़ाते हुए करनाल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रैली की तैयारियों के लिए बनाए गए जिला प्रभारियों और हलका प्रभारियों के साथ मंत्रणा की गई। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला ने कहा कि रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। उन्होंने कहा कि अहीरवाल में वाली जेजेपी की रैली कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी रैली की तैयारियों में जी-जान से जुट जाए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सामने



आ रही गड़बड़ियों को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी भाजपा सरकार आज सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग की गलतियां छिपाने में लगी हुई है और इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयोग इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। वहीं इससे पहले वोट गड़बड़ियों वाले हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में जाकर चुनाव आयोग ने प्रवक्ता की तौर पर भाजपा सरकार का पक्ष लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए जल्दबाजी की और इसका खामियाजा वोट काटे गए करोड़ों मतदाताओं को भुगतना पड़ा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सवाल किया कि अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी जायज मतदाता का वोट कट गया है तो उसे दोबारा वोट बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा ?, चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज मतदाता को अपना वोट दोबारा बनवाने के लिए केवल फार्म 6ए का ही विकल्प है, जबकि इसी फार्म में ही मतदाता को यह शपथ देनी होती है कि वो पहली बार अपना वोट बनवा रहा है जो कि अपने आप में कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि उक्त मतदाता से आयोग झूठी घोषणा करवा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें यह भी आशंका है कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले डबल वोट बनवाए गए। अब उन्हीं डबल वोटों को एसआईआर के जरिए काटाकर बचाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेजेपी अपने स्तर पर प्रदेशभर में साल 2022, 2024 और 2026 की मतदाता सूचियों का मिलान कर तथ्यों को हरियाणा की जनता के सामने लाएगी। एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार को सड़क पर उतरकर मांगना अराजकता नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की आवाज को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है या फिर अपनी बात रखता है तो उसकी वीडियो को सोशल मीडिया से ही हटा दिया जाता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने सीएम से सवाल पूछा था कि ढाई साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में कितने उद्योग स्थापित करवाए ? सरकार ने इस सवाल का जवाब देने की बजाय वीडियो ही डिलीट करवा दिया। उन्होंने कहा कि जब-जब जनता की आवाज का गला घोटा गया

संक्षिप्त डायरी

युवाओं से संवाद कर दी गई एसआईआर की जानकारी

अनप्लग इंडिया

पीलीभीत। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने तथा मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत की ओर से सोमवार को एक निजी इंस्टीट्यूट में युवा संवादकार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम अपने मताधिकार को जानें रही। कार्यक्रम में युवा आइकन सुमित जैसवार ने युवाओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना है। इसके तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और अपात्र व्यक्तियों के नामों की नियमानुसार जांच एवं आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का सही एवं अद्यतन होना बेहद जरूरी है। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार और आसपास के लोगों को मतदाता सूची में नाम की जांच करने तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराने के लिए जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी शिवम शर्मा ने युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी।

70 घंटे बाद साबिर का नामांकन निरस्त, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व सचिव पद प्रत्याशी आज देंगे फाइनल स्पीच

अनप्लग इंडिया

अलीगढ़। एएमयू छात्रसंघ चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशी मंगलवार को यूनियन हॉल की छत से फाइनल स्पीच देंगे। पांच मिनट के भाषण में प्रत्याशियों को न केवल राष्ट्र निर्माण में छात्र नेतृत्व का योगदान बताना होगा, बल्कि विद्यार्थियों के सामने अपने विजन और प्राथमिकताओं को भी बताना होगा। एएमयू छात्रसंघ चुनाव में नामांकन निरस्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूनानी मेडिसिन संकाय से एएमयू कोर्ट सदस्य पद के प्रत्याशी मोहम्मद साबिर हुसैन का नामांकन करीब 70 घंटे बाद रद्द कर दिया गया। खास बात यह है कि 29 अक्तूबर को जांच में उनका परचा वैध पाया गया था। इसके बाद 31 अक्तूबर को उन्हें चुनाव के लिए क्रमांक संख्या छह भी आवंटित कर दिया गया था। मोहम्मद साबिर हुसैन ने 29 अक्तूबर को एएमयू कोर्ट सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके परचे पर कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि साबिर आठ साल से अधिक समय से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वह चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रखते। इस मुद्दे पर विद्यार्थियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया और नामांकन रद्द करने की मांग उठाई। 29 अक्तूबर को शाम चार बजे नामांकन पत्रों की जांच हुई, जिसमें साबिर का परचा सही पाया गया। इसके दो दिन बाद उन्हें क्रमांक संख्या छह आवंटित कर दिया गया। हालांकि, सोमवार सुबह 10 बजे मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि जांच के बाद नामांकन रद्द करने का निर्णय लिया गया। एएमयू में प्रचार करते प्रत्याशीफैसले के बाद यूनियन हॉल पर हंगामा नामांकन निरस्त होने की सूचना मिलते ही विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई। कुछ विद्यार्थियों ने यूनियन हॉल के गेट पर ताला लगाने की कोशिश की। इससे परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। मामले को लेकर एएमयू कोर्ट के कुछ प्रत्याशी कुलपति से मिलने भी पहुंचे। विद्यार्थियों का सवाल है कि जब नामांकन पत्रों की जांच में परचा वैध पाया गया और प्रत्याशी को चुनावी क्रमांक भी आवंटित कर दिया गया था, तो करीब 70 घंटे बाद उसे निरस्त करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया और नामांकन जांच को लेकर कैंपस में चर्चा तेज हो गई है। एएमयू छात्रसंघ चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशी मंगलवार को यूनियन हॉल की छत से फाइनल स्पीच देंगे। पांच मिनट के भाषण में प्रत्याशियों को न केवल राष्ट्र निर्माण में छात्र नेतृत्व का योगदान बताना होगा, बल्कि विद्यार्थियों के सामने अपने विजन और प्राथमिकताओं को भी बताना होगा। यूनियन हॉल की छत पर कार्यक्रम के लिए पंडाल लगाया गया है। छात्राओं के लिए बैठने की जगह दायीं ओर होगी। सामने छात्र होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि दोपहर 2:15 बजे से प्रत्याशियों की फाइनल स्पीच शुरू होगी। प्रत्येक प्रत्याशी को पांच मिनट और एक मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। प्रत्याशी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत किसी भी भाषा में अपनी बात रख सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात रहेगी।

जिम कॉर्बेट में सीडीएफयूपी की वार्षिक आम सभा, नई दवा नीति और कानूनी प्रावधानों पर हुई चर्चा

एजेंसी

अलीगढ़। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश (सीडीएफयूपी) की वार्षिक आम सभा और सतत शिक्षा कार्यक्रम (कंटीन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम) उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में आयोजित हुआ। दवा कारोबार में पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब बिना बिल की दवाओं की खरीद-बिक्री पर सख्ती बरतने की तैयारी है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश (सीडीएफयूपी) की वार्षिक आम सभा और सतत शिक्षा कार्यक्रम (कंटीन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम) उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे पदाधिकारियों को नई दवा नीति और प्रस्तावित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। फेडरेशन के महामंत्री सुरेश गुप्ता ने सभी जिला इकाइयों को निर्देशित किया कि एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की बिना डॉक्टर के पर्चे और बिना बिल के खरीद-बिक्री तत्काल बंद कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं का संगठन किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं करेगा। दवा कारोबार की छवि को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा। बैठक में संगठन के सदस्य संदीप चतुर्वेदी ने कहा कि दवा कारोबारियों का उत्पीड़न और शोषण करने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं किया जाएगा। वहीं, अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक में हुई चर्चा के आधार पर जिले के सभी दवा विक्रेताओं से बिना बिल की दवाओं की खरीद-बिक्री से दूर रहने और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का पूरा लेखा-जोखा रखने की अपील की है। कार्यक्रम में अलीगढ़ की ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सिंह, महामंत्री आलोक वार्ष्णेय, रीजन महामंत्री भूपेंद्र वार्ष्णेय, संगठन मंत्री अनिल वर्मा और बृजेश वार्ष्णेय मौजूद रहे।

अंडरवियर में मोबाइल छिपाकर लाया डिवाइस, नकल का ऐसा तरीका; चकरा जाएगा दिमाग

एजेंसी

एटा। मैनपुरी में पीईटी परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ बड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े गए अभ्यर्थी को न्यायालय ने जेल भेज दिया। अभ्यर्थी ने पूछताछ में बताया कि वह डिवाइस अंडरवियर में छिपाकर लाया था। पुलिस के अनुसार, प्रयागराज निवासी उसके एक दोस्त ने नकल के लिए डिवाइस दी थी। आगरा एसटीएफ ने भी उससे पूछताछ की है और अब दोस्त की भूमिका की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) में रविवार को ब्लूटूथ बड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़े अभ्यर्थी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को अभ्यर्थी ने बताया कि प्रयागराज के रहने वाले उसके एक दोस्त ने उसे नकल करने के लिए डिवाइस दी थी। मामले की जानकारी मिलने पर आगरा से आई एसटीएफ की टीम ने भी उससे पूछताछ की थी। रविवार को कचहरी रोड स्थित कुंवर रामचंद्र सिंह लाल सिंह कन्या इंटर कॉलेज में पीईटी की प्रथम पाली की परीक्षा चल रही थी।

पीलीभीत के नूरानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेलीकॉप्टर से उतरते ही गूंजे जयकारे

अनप्लग इंडिया



पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील स्थित नूरानपुर गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां गोरक्षपीठ से जुड़े प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर में आयोजित नौ दिवसीय श्री रामकथा के समापन अनुष्ठान और पूर्णाहुति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। राज्य के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ प्रमुख के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह और भक्तिमय माहौल देखा गया। मंगलवार दोपहर लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नूरानपुर गांव में शिव मंदिर के ठीक समीप बनाए गए विशेष हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर के उतरते ही कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित साधु-संतों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और हजारों की संख्या में आए ग्रामीणों ने जयघोष के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भक्तिमय माहौल में हुआ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व ही नूरानपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में उत्सव जैसा वातावरण बन चुका था। गोरक्षपीठ से जुड़े इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में पिछले नौ दिनों से दिव्य रामकथा का आयोजन चल रहा था, जिसका समापन मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। जैसे ही मुख्यमंत्री हेलीपैड से उतरकर कार्यक्रम स्थल और मंदिर परिसर की ओर बढ़े, पूरा क्षेत्र जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनभेदी नारों से गुंजायमान हो उठा। आश्रम परिसर में मंच और पूजा-अर्चना स्थल को फूलों तथा झंडियों से भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित शीर्ष साधु-संतों, धमार्चार्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर और झुकाकर उपस्थित जनसमूह, संतों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। गोरक्षपीठ और नूरानपुर शिव मंदिर का विशेष संबंध नूरानपुर स्थित शिव मंदिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से गोरक्षपीठ (गोरखपुर) से सीधे जुड़ा हुआ है। गोरक्षपीठ परंपरा के तहत समय-समय पर यहाँ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का आयोजन होता रहता है। नौ दिनों तक चली इस श्री रामकथा में प्रतिदिन आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों श्रद्धालु प्रभु राम के आदर्शों और कथा का श्रवण करने पहुंचते थे। मंगलवार को रामकथा के अंतिम दिन विशेष हवन, पूजन और पूर्णाहुति का आयोजन किया गया था। गोरक्षनाथ पीठ के प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन-पूजन किया और देश तथा प्रदेश की समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने रामकथा के समापन अवसर पर आयोजित हवन कुंड में आहुति दी और संतों के साथ धार्मिक अनुष्ठान पूरा किया। श्रद्धालुओं और संतों का विशाल समागम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुबह से ही नूरानपुर गांव की ओर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। पीलीभीत जिले के अलावा आसपास के जिलों जैसे शाहजहांपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी और बदायूं से भी बड़ी संख्या में संत-महात्मा और ग्रामीण इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंचे थे। मंदिर परिसर में स्थापित विशाल पंडाल श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। हर आयु वर्ग के लोग, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे, मुख्यमंत्री को देखने और उनके विचार सुनने के लिए आतुर नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था का खाका इस तरह तैयार किया गया था कि परिंदे भी पर न मार सकें। सुरक्षा बल में लगभग 1600 पुलिसकर्मियों के साथ-साथ प्रांतीय सशस्त्र बल की एक पूरी कंपनी तैनात की गई थी। महिला उपनिरीक्षकः 38 महिला सब-इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई। हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबलः 707 मुख्य आरक्षी और आरक्षी जवानों ने सुरक्षा घेरा संभाला। महिला आरक्षीः महिला श्रद्धालुओं की जांच और सुरक्षा के लिए 124 महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया था। हेलीपैड से लेकर मुख्य कथा स्थल, मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही।

डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत; राहगीरों ने देखा शव तो दी पुलिस को जानकारी



अनप्लग इंडिया

मिजार्पुर । मिजार्पुर जिले में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक लहंगपुर से अपने घर लौट रहा था। मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे राहगीरों ने सड़क पर उसका शव पड़ा देखा। वाराणसी-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजापुर गांव के पास सोमवार की देर रात बाइक डिवाइडर से टकराने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक लहंगपुर से अपने घर लौट रहा था। मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे राहगीरों ने सड़क पर उसका शव पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान कर परिजनों को घटना की सूचना दी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के करनपुर दहवा गांव निवासी सुनील सोमवार की देर रात बाइक से लहंगपुर से घर लौट रहा था। राजापुर गांव के पास लहंगपुर पुलिस चौकी के निकट उसकी बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर से उसके सिर में गंभीर चोट आई। सुबह राहगीरों की नजर उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बाइक और युवक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनील छह भाई-बहनों में सबसे छोटा था।

आईआईटी बीएचयू में आएंगी वित्तमंत्री, जारी करेंगी 250 रुपये का स्मारक सिक्का

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। आईआईटी बीएचयू में आज वित्तमंत्री सीतारमण आएंगी। वह 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। कर्नाटक के संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर विमोचन होगा। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को आईआईटी बीएचयू में कर्नाटक के जाने माने संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होंगी। मुत्तुस्वामी की स्मृति में वित्तमंत्री 250 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के तीन महान संगीतकारों की त्रिमूर्ति में दीक्षितर का विशिष्ट स्थान है। आईआईटी बीएचयू के आईकेएस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से स्वतंत्रता भवन में अमरा गुरुगुहाः श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250 वर्ष की स्मृति में शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित है। समारोह का उद्देश्य महान संगीतकार के जीवन, संगीत विरासत और भारतीय संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करना है। बीएचयू संगीत एवं मंच कला संकाय के पूर्व प्रमुख प्रो. राजेश शाह का कहना है कि मुत्तुस्वामी का काशी से जुड़ाव रहा है। वर्ष 1775 में जन्मे मुत्तुस्वामी दीक्षितर का भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम है। वे त्यागराज और श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत की महान त्रिमूर्ति के सदस्य थे। संगीतकार, गायक और वीणा वादक के रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कर्नाटक संगीत को समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में विविध रागों का विस्तार, मंदिरों और देवी-देवताओं का वर्णन और भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की झलक मिलती है। उनकी अनेक रचनाओं में प्रयुक्त गुरुगुहा उनकी विशिष्ट संगीत पहचान है। आज भी उनकी रचनाएं कर्नाटक संगीत की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। भारतीय संगीत, साहित्य और आध्यात्मिक परंपराओं के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती हैं। मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर जारी होने वाला यह सिक्का उनकी अद्वितीय संगीत साधना और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को समर्पित होगा। उनकी अमर रचनाएं आज भी देश-विदेश में संगीत प्रेमियों और कलाकारों को प्रेरित कर रही हैं। मुद्राशास्त्री सुधीर लुणावत, बीकानेर के अनुसार, मुत्तुस्वामी की स्मृति में जारी किया जाने वाला स्मारक सिक्का भारत सरकार की मुंबई टकसाल में तैयार किया गया है। सिक्के का कुल वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जस्ता होगा। यह सिक्का सामान्य प्रचलन में जारी नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री के विमोचन के बाद इसे भारत सरकार की टकसाल की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्धता के अनुसार खरीदा जा सकेगा।

शिक्षक ने स्कूल की छत पर लौकी तोड़ने भेजा, छात्र की हाईटेंशन तार के करंट से मौत

अनप्लग इंडिया

बलिया । बलिया में स्कूल की छत पर लौकी तोड़ने गए चौथी के छात्र की हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। आरोप है कि शिक्षक ने उसे लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजा था। बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के कनैला दलित बस्ती पोखरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। विद्यालय की छत पर लौकी तोड़ने गए कक्षा चार के छात्र अरशद (10) की हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को लौकी तोड़ने के लिए छत पर भेजा था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शिक्षकों को बंधक बना लिया। करीब चार घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गड़वार, सुखपुरा, फेफना और चितबड़ागांव थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाया तथा शासन से मिलने वाली सहायता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रभारी प्रधानाचार्य विजय शंकर और सहायक शिक्षक अनिल कुमार को निलंबित कर दिया है, जबकि शिक्षामित्र की सेवा समाप्ति के लिए ग्राम प्रधान को पत्र भेजा गया है। कनैला गांव निवासी इजहार का पुत्र अरशद प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार का छात्र था। वह रोज की तरह सोमवार को विद्यालय गया था। आरोप है कि शिक्षक ने उसे छत पर चढ़कर लौकी तोड़ कर लाने के लिए कहा। लौकी तोड़ते समय छात्र वहां से गुजर रहे हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देख बच्चे चिल्लाने लगे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन संग ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंच गए। शिक्षकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीण हंगामा करने लगे। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग पर अड़े थे। सूचना पर एसडीएम सदर गोपेश तिवारी, बीएसए मनीष कुमार सिंह,बीईओ विशाल यादव, हाइडिल के एसडीओ और सीओ सिटी सतीश शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को शासन से मिलने वाली सहयोग राशि और अन्य मदद के साथ दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्र अरशद अपने माता-पिता की छह संतानों में सबसे छोटा था। वह पढ़ाई में अव्वल था।

पहले दिन यात्रियों में दिखा उत्साह, फर्स्ट एसी में आधी सीटें भरीं

अनप्लग इंडिया



वाराणसी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से वाराणसी से दिल्ली का सफर आसान हो गया है। पहले दिन यात्रियों में गजब का उत्साह दिखा। इस ट्रेन के चलने से शिवगंगा एक्सप्रेस और नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भार कम हुआ है। देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सोमवार को कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई। पहले दिन फर्स्ट एसी कोच में आधे से अधिक सीट वाराणसी से ही भरी दिखी जबकि सेकंड और थर्ड एसी में रिजर्वेशन कराने वालों को सोमवार शाम तक सीट मिली। इस ट्रेन के चलने से बनारस स्टेशन से चलने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस और नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भार कम हुआ है। सामान्य दिनों में इन दोनों ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट लंबी रहती है। 27421 वंदेभारत स्लीपर ट्रेन रात 8.50 बजे रवाना हुई। पहले दिन आईआरसीटीसी की ओर से ट्रेन में यात्रियों का स्वागत किया गया। उधर, यात्री भी हर हर महादेव के जयघोष के साथ सफर पर निकले। रिजर्वेशन की बात करें तो फर्स्ट एसी पहले फुल हो जा रही है। जबकि सेकंड, थर्ड एसी में ट्रेन के चलने से पहले तक लोग सीट पा जा रहे हैं। पहले दिन भी ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि, पहले दिन निर्धारित समय रात 8.50 बजे से 5 मिनट की देरी से स्लीपर ट्रेन को रवाना किया गया, प्रयागराज में इसका निर्धारित समय रात 10.35 बजे है, लेकिन यह ट्रेन 10 मिनट पहले ही पहुंच गई। शिवगंगा समेत तीन ट्रेनों में मिला कंफर्म टिकट शिवगंगा समेत तीन ट्रेनों में लोगों को सोमवार को भी कंफर्म सीट मिल गई। इसमें वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली 04209 वाराणसी से रात 10.15 बजे दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन में स्लीपर कोच में 9.30 बजे तक 320 कंफर्म सीट थी। जबकि 3 एसी में भी 225 और सेकंड एसी में 23 सीट कंफर्म दिख रही थी। 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर दिन बनारस स्टेशन से रात 11.10 बजे चलती है। इस ट्रेन में भी 9.30 बजे तक थर्ड एसी में 105, सेकंड में 31 जबकि फर्स्ट एसी में 4 सीट खाली दिख रही थी।

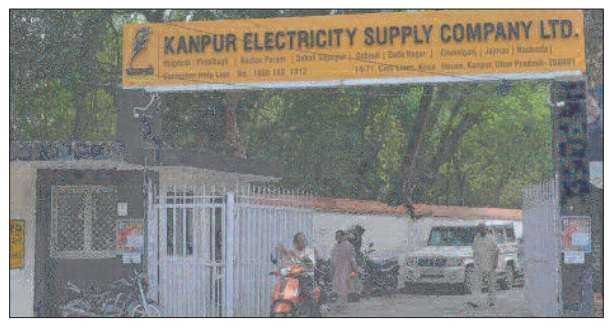
शीतलहर के दिनों के तेवर ठंडे करेगा अल नीनो

अनप्लग इंडिया



कानपुर । और आसपास के क्षेत्रों में इस बार अल नीनो के प्रभाव के चलते कड़ाके की ठंड और शीतलहर के दिन कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अमूमन 20 दिन तक रहने वाली शीतलहर की अवधि घटकर 13 से 15 दिन तक सिमट सकती है, और सर्दियों में तापमान सामान्य से 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक कानपुर में अल नीनो के प्रभाव से इस बार शीत लहर के दिन कम हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर परिक्षेत्र में औसतन 20 दिन रहने वाली शीतलहर की अवधि पांच से सात दिन घट सकती है। यानी इस बार शीतलहर के दिन 13 से 15 तक सिमट सकते हैं। वहीं, सर्दियों में तापमान सामान्य औसत से 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। जाड़े में शीतलहर उस स्थिति को कहते हैं, जब तापमान सामान्य औसत से चार से पांच डिग्री तक नीचे चला जाता है। अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसका प्रभाव मानसून के साथ सर्दियों पर भी पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि अल नीनो वाले वर्षों में ठंड सामान्य से कम रहती है। इसका असर नवंबर से फरवरी के बीच तापमान पर दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक अल नीनो वर्षों में सर्दियों का औसत तापमान सामान्य से 0.5 से 1.5 डिग्री तक अधिक बढ़ा रहता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में यह अंतर दो डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे रातों का तापमान भी सामान्य से 0.8 से एक डिग्री तक ऊपर रह सकता है और कड़ाके की ठंड की अवधि घट जाती है। नोडल अधिकारी ने बताया कि इस साल अल नीनो के प्रभाव के कारण देश में अक्तूबर का औसत अधिकतम तापमान इतिहास में सबसे गर्म 32.43 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.06 डिग्री अधिक था। अल नीनो के प्रभाव से उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाने वाले पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाते हैं। पहाड़ों पर सामान्य से बहुत कम बर्फबारी होती है। बर्फीली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में नहीं चलतीं हैं। हवाओं का रुख बदलने से कड़ाके की ठंड का अहसास कम होता है। तापमान सामान्य से एक डिग्री भी अधिक रहने पर फसलों पर असर पड़ सकता है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए लंबे समय तक कम तापमान जरूरी होता है।

आचार्यनगर में केस्को का सघन चेकिंग अभियान, पांच परिसरों में पकड़ी बिजली चोरी, एफआईआर दर्ज



अनप्लग इंडिया

कानपुर । आचार्यनगर में केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ जोरदार सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने विभिन्न परिसरों में अवैध रूप से बिजली जलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बिजली चोरी में लिप्त पाए गए पांचों गृहस्वामियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कानपुर में लाइन लॉस वाले क्षेत्र आचार्यनगर में सोमवार को केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने पांच परिसर में बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने जीवनलाल का हाता निवासी कृष्णा, देवीदीन का हाता निवासी किरन, तान्या, भन्नानापुरवा में जय, विजय और अजय परिहार के घर बिजली चोरी होते मिली। टीम को आचार्यनगर में अमर कौल के घर चोरी से बिजली जलती मिली। इन सभी के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।



कीर्ति सुरेश ने नहीं की बॉलीवुड में आने की जल्दबाजी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश इन दिनों अपनी आने वाली सीरीज 'अक्का' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस सीरीज में वह अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ दिखाई देंगी। बता दें कि साउथ अभिनेत्री कीर्ति ने 2024 में वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में आने और काम करने को लेकर बात की। कीर्ति ने बताया कि वह हिंदी सिनेमा में काम करना चाहती थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह चाहती थीं कि सब कुछ सही समय पर अपने आप हो।

क्या बोलीं कीर्ति सुरेश

कीर्ति ने कहा, 'मैं निश्चित रूप से किसी समय हिंदी सिनेमा में काम करना चाहती थी और आखिरकार ऐसा हुआ। इसकी शुरुआत 'अक्का' से हुई। इस बीच 'बेबी जॉन' आई और उसके बाद मैंने राजकुमार राव के साथ 'रफ्तार' नाम की फिल्म की। यह फिल्म भी जल्द रिलीज होनी चाहिए।'

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मैं किसी रेस में नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी फिल्में करनी हैं। मैं वही काम कर रही हूं जो मुझे पसंद है। हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका भी मुझे इसी तरह मिला। मैं इसके पीछे भाग नहीं रही थी। सब कुछ अपने आप सही समय पर हुआ और अब देखूंगी कि इसे आगे कैसे बढ़ाना है।'

कैसे कीर्ति को मिली 'अक्का'

कीर्ति ने बताया कि धर्मा (निर्देशक) ने मेरी फिल्म 'सानी कायिधम' देखी थी। उसमें मेरा किरदार बेहद मजबूत और बेखौफ था, लेकिन उसके अंदर एक संवेदनशील पहलू भी था। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फिल्म देखी है। तब मैंने उनसे कहा कि अब मैं समझ गई कि आप मुझे यह किरदार क्यों देना चाहते हैं।

कीर्ति और राधिका स्टारर 'अक्का' की कहानी 1980 के दशक में पेरनुरु नाम के एक काल्पनिक राज्य में दिखाई गई है, जहां महिलाओं का दबदबा है। फिल्म की कहानी भवानी (कीर्ति) और रुद्रा (राधिका) नाम की दो ताकतवर महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की अलग-अलग सोच और उनके बीच की दुश्मनी राज्य में सत्ता के समीकरण तय करती है।

'अक्का' का निर्देशन धर्मराज शेट्टी ने किया है। सीरीज में कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे के अलावा तन्वी आजमी, महेश मांजरेकर, अंशुमान पुष्कर और मोनिका पंवार समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस सीरीज का निर्माण वाईआरएफ एंटरटेनमेंट ने किया है।



यशस्वी जायसवाल ने ठोकी धमाकेदार सेंचुरी

साई सुदर्शन फ्लॉप, देवदत्त पडिक्कल का नहीं खुला खाता



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीन मैचों की सीरीज जारी है, जो कि अनाधिकारिक है। इसी के दूसरे मैच में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार सेंचुरी ठोक दी है। हालांकि साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल का बल्ला नहीं चला। इस बीच भारत ने ?न्यूजीलैंड पर अच्छी बढ़त बना ली है।

यशस्वी जायसवाल ने 119 बॉल पर पूरी की अपनी सेंचुरी – यशस्वी जायसवाल ने भारत ए की ओर से खेलते हुए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा किया। उन्होंने केवल 119 बॉल पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। खास बात ये रही कि अपने आक्रामक अंदाज में जायसवाल ने छक्का लगाकर इस मुकाम को हासिल किया। शतक लगाने के बाद जायसवाल और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। इससे पहले इसी सीरीज के पहले मैच में वे पहली पारी में 17 और दूसरी में केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, इसके बाद उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे, जो अब कुछ कम जरूर होंगे।

ICC ODI रैंकिंग में अफगानिस्तान ने पहली बार टॉप-6 में बनाई जगह

श्रीलंका-इंग्लैंड को छोड़ा पीछे, भारत नंबर 1 पर



नई दिल्ली, एजेंसी। अफगानिस्तान की टीम ने वनडे रैंकिंग में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। साल 2009 में अपना पहला वनडे मैच खेलने वाली इस टीम ने पहली बार आईसीसी की वनडे रैंकिंग में टॉप-6 में जगह बना ली है। खास बात यह है कि बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान ने श्रीलंका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन टीमों को पीछे छोड़ते हुए टॉप-6 में पहली बार जगह बनाने में कामयाब रही है। अफगानिस्तान ने पिछले महीने यूएई में वनडे ट्राई सीरीज जीती थी। हाल ही में इस टीम ने हांगकांग सुपर सिक्सेस का खिताब अपने नाम किया था।

अब तक 96 वनडे मैच जीत चुकी है टीम इंडिया – साल 2009 में वनडे क्रिकेट में कदम रखने के बाद से अफगानिस्तान ने इस फॉर्मेट में कुल 191 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 96 मैचों में जीत हासिल की है। इन 17 सालों के शानदार सफर और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर ही आज अफगानिस्तान की टीम रैंकिंग में मजबूत स्थिति में पहुंच पाई है। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम के भी रैंकिंग में 94 अंक हैं, लेकिन वह खिसककर सातवें स्थान पर आ गई है। श्रीलंका को लाहौर में हुई वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल से पहले भी उसे इंग्लैंड के हाथों 55 रनों से शिकस्त मिली थी। इसके अलावा, रैंकिंग में इंग्लैंड 93 अंकों के साथ आठवें, बांग्लादेश 81 अंकों के साथ नौवें और वेस्टइंडीज 79 अंकों के साथ दसवें स्थान पर है।

वनडे रैंकिंग में टॉप पर है टीम इंडिया – मेंस वनडे रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर बना हुआ है और 115 अंकों के साथ टॉप पर है। भारत ने अपनी पिछली वनडे सीरीज घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी। अब उसे 4 नवंबर से न्यूजीलैंड में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। इस रैंकिंग में न्यूजीलैंड 109 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि साउथ अफ्रीका (104 अंक) तीसरे, पाकिस्तान (104 अंक) चौथे और ऑस्ट्रेलिया (102 अंक) पांचवें नंबर पर हैं।

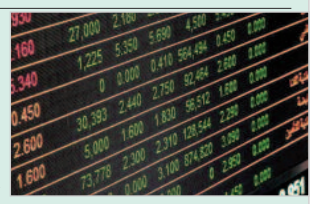
मुकेश अंबानी ने रचा कीर्तिमान, एक दिन में 6.3 अरब डॉलर कमाए

रिलायंस के दमदार तिमाही नतीजों और शेयर में जोरदार उछाल से संपत्ति बढ़ी

मुंबई । रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एक ही दिन में 6.3 अरब डॉलर (लगभग 55,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्ति अर्जित कर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति का गौरव हासिल किया है। यह बढ़ोतरी उनकी प्रमुख कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजों के बाद शेयर में आई जोरदार तेजी का परिणाम है। फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की ताजा सूची के अनुसार मुकेश अंबानी अब 88.8 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 23वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत के सबसे धनी शख्स बन गए हैं। इस सूची में गौतम अदाणी 79.12 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 26वें स्थान पर हैं। संपत्ति में इस वृद्धि के मामले में वैश्विक स्तर पर स्पेन के अमानसियो ओर्टेगा (1.7 अरब डॉलर) और चीन के झोंग शांशान (1.5 अरब डॉलर) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 11.64 प्रतिशत चढ़कर 1,299 रुपये पर बंद हुआ, जो छह साल से अधिक समय में इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। यह उछाल कंपनी के सितंबर तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया, जिसमें एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33.8 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 29,550 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। कंपनी के तेल से रसायन और दूरसंचार व्यवसायों में मजबूत प्रदर्शन ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। कंपनी के तेल से रसायन (ओ2सी) कारोबार में मजबूत प्रदर्शन और दूरसंचार व्यवसाय में वृद्धि ने खुदरा कारोबार की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति की भरपाई कर दी।

एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक का शेयर आठ फीसदी बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।



अपशिष्ट जल शोधन समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का शेयर अपने 330 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब आठ प्रतिशत की बढ़त के साथ मंगलवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने निर्गम मूल्य से 7.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 354.05 रुपये पर कारोबार शुरू किया। एनएसई में यह 7.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 355.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,161.69 करोड़ रुपये रहा। एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह गुरुवार को बोली के अंतिम दिन 9.47 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 668 करोड़ रुपये के आईपीओ का मूल्य दायरा 313 से 330 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी की योजना नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की है।

ग्लेन मैक्सवेल ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले कुल 286 मैच



नई दिल्ली, एजेंसी। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनके शानदार इंटरनेशनल करियर का अंत हो गया। मैक्सवेल ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग से खेल जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिना जाता था। वह हाल ही में ETPL में खेलते हुए नजर आए थे।

2012 में मैक्सवेल ने किया था इंटरनेशनल डेब्यू – ग्लेन मैक्सवेल ने साल 2012 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह अपनी ताबड़तोड़ और आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर बहुत कम समय में ही क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 149 वनडे मैचों में कुल 3990 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे में उनका खेलने का तरीका बेहद आक्रामक था और उनका स्ट्राइक रेट 126.71 का रहा। ह्यष्ठढ्ढ में उनका सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 201 रन रहा, जो उन्होंने साल 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ एक मुश्किल समय में ऐतिहासिक पारी खेलते हुए बनाया था।

वनडे में मैक्सवेल का प्रदर्शन रहा शानदार – मैक्सवेल सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर भी थे। उन्होंने वनडे में 77 और टी20 इंटरनेशनल में 51 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा फील्डिंग में भी उन्होंने कमाल किया था। उन्हें अपने दौर के सबसे बेहतरीन फील्डरों में गिना जाता था। टी20 क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 130 मैचों में 2897 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। इस फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 154 से भी ज्यादा का था। वहीं टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7 मैच खेलकर 1 शतक की मदद से कुल 339 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए वह कुल 286 इंटरनेशनल मैच खेलने में कामयाब रहे।

आईपीएल में भी कई फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं मैक्सवेल – इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी ग्लेन मैक्सवेल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आईपीएल में भी मैक्सवेल का जलवा खूब देखने को मिला। उन्होंने आईपीएल में 141 मैच खेलकर 2819 रन बनाए। मैक्सवेल दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और आरसीबी जैसी बड़ी टीमों के लिए खेल चुके हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की 2015 और 2023 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी अहम हिस्सा रहे थे।

प्रेमा रावत ने तोड़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

14 गेंदों में फिफ्टी जड़कर रचा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेटर प्रेमा रावत ने महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारतीय सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में उत्तराखंड टीम की तरफ से खेलते हुए प्रेमा ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों में ही 50 रन ठोक डाले। इस तरह प्रेमा ने पाकिस्तानी खिलाड़ी फातिमा सना का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर यह नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है।

फातिमा सना ने 15 गेंदों में लगाया था अर्धशतक – इससे पहले महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड फातिमा सना के नाम था, जिन्होंने 15 गेंदों पर फिफ्टी बनाई थी। अब प्रेमा रावत ने सिर्फ 14 गेंदों में यह कमाल करके पूरी दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि प्रेमा ने अपनी इस आतिशी पारी में 50 में से 48 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से ही बना डाले। प्रेमा ने इस पारी में 357.14 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और एक नया इतिहास रच दिया।

उत्तराखंड ने 89 रनों से जीता मुकाबला – मैच की बात करें तो, प्रेमा रावत की शानदार पारी की बदौलत उत्तराखंड की टीम ने 20 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद भी सिर्फ 98 रन ही बना पाई। इस तरह उत्तराखंड ने यह मैच 89 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। प्रेमा रावत के अलावा उत्तराखंड की तरफ से राघवी बिस्ट ने नाबाद 72 रन और करीना ने 44 रनों की बेहतरीन पारियां खेलीं। वहीं नीलम भारद्वाज ने 19 रनों का योगदान दिया। हैदराबाद के खिलाफ इस मैच में प्रेमा रावत ने गेंदबाजी में भी अपने योगदान दिया। प्रेमा रावत ने इस मैच में 2 विकेट चटकाए। प्रेमा ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 12 रन देकर ये 2 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, निशा और सफीना को भी 2-2 विकेट मिले, जबकि पूजा राज और करीना ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों की मांग फाइनल से भी ज्यादा

वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीटें 34 हजार, आवेदन आए 84 लाख; जोहान्सबर्ग में मुकाबला

नई दिल्ली । वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। 10 अक्टूबर के इस मैच के टिकटों के लिए 84 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जोहान्सबर्ग के स्टेडियम की दर्शक क्षमता सिर्फ 34 हजार है। यानी उपलब्ध सीटों के मुकाबले करीब 247 गुना ज्यादा आवेदन आए हैं।

फाइनल के लिए भी 79 लाख आवेदन – टिकटों की मांग के मामले में भारत-पाकिस्तान मुकाबला पहले नंबर पर है। आईसीसी के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान मैच के लिए कुल 83,97,294 टिकट आवेदन मिले हैं। 21 नवंबर को इसी स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के लिए 79,00,944 रजिट्रेशन हुए हैं।

21 नवंबर तक टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे – वर्ल्ड कप के टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा और मांग ज्यादा होने पर कंप्यूटराइज्ड रैंडम लॉटरी से टिकट खरीदने के लिए आवेदकों का चयन किया जाएगा। यह पहले आओ-पहले पाओ वाला सिस्टम नहीं है।

193 देशों से मिले 12 करोड़ आवेदन – आईसीसी को अब तक टूर्नामेंट के लिए 193 देशों से 12 करोड़ से ज्यादा टिकट आवेदन मिले हैं। साउथ अफ्रीका में होने वाले 41 मैचों के लिए ही 10.5 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें मेजबान टीम के मैचों के लिए करीब 2.6 करोड़ आवेदन आए हैं।

24 साल बाद अफ्रीका में होगा वर्ल्ड कप – वनडे वर्ल्ड कप 24 साल बाद अफ्रीकी धरती पर लौटेगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 12 वेन्यू पर कुल 57 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए 12 वेन्यू में से 8 साउथ अफ्रीका, 3 जिम्बाब्वे और 1 नामीबिया में है। नामीबिया पहली बार मेंस के सीनियर वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेगा।

'सुबह उठकर सोचता हूं आखिर इतनी मेहनत क्यों करूं'

टीम इंडिया से नजरअंदाज किए जाने पर छलका सरफराज खान का दर्द

नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया से बाहर चल रहे घरेलू क्रिकेट के धुरंधर बल्लेबाज सरफराज खान ने एक बार फिर अपनी निराशा खुलकर जाहिर की है। रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब सुबह उठकर उनके मन में यही सवाल आता है कि जब टीम में मौका ही नहीं मिलना है, तो वह इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हैं। सरफराज ने बताया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी पुरानी रूटीन को फॉलो करते हैं। वह भारत के लिए खेल चुके हैं और मुंबई के लिए लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम में वापसी का इंतजार लंबा होता जा रहा है।



पिता से मिलती है आगे बढ़ने की प्रेरणा – न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से सरफराज ने बताया कि मुश्किल समय और निराशा के दौर में उनके पिता नौशाद खान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा हैं। सरफराज का कहना है कि जब कभी उनके मन में यह सवाल उठता है कि वह इतनी मेहनत क्यों करें, तब वह अपने पिता को कड़ी मेहनत करते हुए देखते हैं। पिता को देखकर उन्हें फिर से मैदान पर उतरने और उनके लिए रन बनाने की प्रेरणा मिल जाती है। अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे मिलना हो तो उसे घर जाने की जरूरत नहीं है, वह सुबह 6 बजे सीधे आजाद मैदान या क्रॉस मैदान पहुंच जाए, सरफराज वहीं मिलेंगे।

चयनकर्ताओं को सिर्फ घरेलू पिचों के लिए उपयोगी लगती है मेरी सेवाएं- सरफराज

फरवरी 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज ने अब तक अपने सभी छह टेस्ट मैच देश में यानी घरेलू मैदानों पर ही खेले हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनकी सेवाएं सिर्फ भारत की घरेलू पिचों पर ही देख रहा है, हालांकि चयनकर्ताओं ने उन्हें इस बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं बताया है। विदेशी दौरों पर मौका न मिलने पर हैरानी जताते हुए सरफराज ने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दौरों का जिक्र किया, जहां उन्होंने 'इंडिया ए' की तरफ से खेलते हुए अभ्यास मैचों में शानदार शतक जड़े थे।

संक्षिप्त समाचार

ऑस्ट्रेलिया में सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत

मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सप्ताहांत के दौरान हुए सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई। इनमें चार लोग मोटरसाइकिल चला रहे थे और तीन कार चला रहे थे। रविवार शाम मेलबर्न के ब्राइटन ईस्ट इलाके में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक और बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार एक बच्चा मामूली रूप से घायल हुआ। इससे पहले शनिवार को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में एक वाहन की टक्कर से 75 साल की महिला की मौत हो गई थी। वहीं, जिलॉन्ग के पास ई-बाइक और कार की टक्कर में दो किशोर घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है।

नेपाल: बर्फबारी में फंसे छह भारतीय पर्यटकों का रेस्क्यू

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के शे-फोक्सुंडो नेशनल पार्क इलाके में भारी बर्फबारी के कारण फंसे छह भारतीय पर्यटकों को सोमवार सुबह सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी एक नवंबर से संपर्क से बाहर थे। पर्यटकों को निजी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। फिलहाल सभी का डोल्पा जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। ये पर्यटक शे-फोक्सुंडो झील घूमने गए थे। लौटते समय भारी बर्फबारी के कारण नुमला और वागला दर्रे में फंस गए। खराब मौसम के चलते रविवार को सेना का हेलीकॉप्टर भी उन्हें बचाने में नाकाम रहा था। प्रशासन ने पहले ही इलाके में भारी बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों को वहां न जाने की चेतावनी दी थी।

'बांग्लादेशी कपड़ा श्रमिकों का प्रदर्शन, कारखाने बंद

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में कपड़े बनाने वाले श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने वेतन की समीक्षा के लिए वेतन बोर्ड के गठन का एलान किया है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे इन प्रदर्शनों के चलते देश भर में 500 से अधिक कारखाने बंद करने पड़े हैं, और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यह विवाद उस उद्योग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है, जो लगभग 40 लाख श्रमिकों को रोजगार देता है। बांग्लादेश में 80% से अधिक निर्यात आय पैदा करता है और दुनिया के कई बड़े पश्चिमी ब्रांडों को कपड़े सप्लाई करता है।

4.2 करोड़ बच्चों को पछाड़ 11 साल की मयार ने जीता अरब रीडिंग चैलेंज

दुबई , एजेंसी। मिस्र की 11 साल की छात्रा मयार मोहम्मद ने दुबई में आयोजित 8वें 'अरब रीडिंग चैलेंज' में दुनिया भर के 4.02 करोड़ से अधिक छात्रों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। दुबई ओपेरा में आयोजित समारोह में यूएई के उपराष्ट्रपति, पीएम व दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मयार को इस ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता को जीतने पर मयार को इनाम के रूप में 5 लाख दिरहम (लगभग 1.14 करोड़ रुपये) की राशि मिली है। मिस्र की एक प्राइमरी स्कूल की छात्रा मयार ने दुबई में फाइनल स्टेज तक पहुँचने और उसे जीतने के लिए अलग-अलग विषयों की दर्जनों किताबों को न केवल पढ़ा, बल्कि उनका गहराई से विश्लेषण भी किया। प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि दूसरे स्थान के लिए तीन छात्रों के बीच टाई हो गया।

ट्रंप ने किसानों को दिया 1.42 लाख करोड़ का पैकेज

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी कृषि उत्पादकों के लिए 15 अरब डॉलर(1.42 लाख करोड़ रुपये) की वित्तीय मदद और योजनाओं का वादा किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को डीजल और उर्वरक की उन बढ़ी हुई लागतों से राहत दिलाना है, जिन्हें उन्हें मुख्य रूप से ट्रंप के टैरिफ और ईरान के साथ युद्ध के कारण भुगतना पड़ा है। ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए ट्रंप ने रविवार को आयोवा और कंसास का दौरा भी किया। कुल 15 अरब डॉलर में से आधे से अधिक यानी 8 अरब डॉलर किसानों को मिलने वाले एकमुश्त भुगतान के रूप में दिए जाएंगे।

कांग्रेस के साथ जो जाता है, डूब जाता है: शिवराज सिंह चौहान

लखनऊ , एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत मंगलवार को एनडीए गठबंधन ने लखनऊ में पदयात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा।

पदयात्रा के दौरान केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आपने हमें छेड़ दिया है। आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, देश में 49 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनावी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाता तो झूठ फैलाकर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार इसी चिंता में लगा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए।

इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर है। तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की राजनीतिक जमीन कमजोर हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसी पार्टी और नेता हैं, जिनके साथ जो जाता है, वह भी डूब जाता है। डूबने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि चुनाव नहीं जीत पाने के कारण कांग्रेस और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को गुंडातंत्र और लूटतंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देश के बंटवारे के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन और 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बांटने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता देश को बांटने और विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगा।



मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मृतकों, दूसरी जगह जा चुके लोगों और फर्जी व डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि करीब एक करोड़ फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। उनके मुताबिक, इससे विपक्ष परेशान है, क्योंकि वह घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए देश के हित में काम करते हैं, जबकि इंडी गठबंधन घुसपैठियों के पक्ष में खड़ा है।

घटिया काम करने पर शर्म आनी चाहिए, गडकरी ने ठेकेदार को लगाई फटकार

- केंद्रीय मंत्री मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखने गए थे वर्धा

वर्धा, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में घटिया सड़क निर्माण को लेकर एक ठेकेदार को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गडकरी सड़क निर्माण में घटिया काम करने को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। गडकरी ठेकेदार से कहते सुनाई दे रहे हैं कि उसे ''इतना घटिया काम करने पर शर्म आनी चाहिए।'' केंद्रीय मंत्री ने ठेकेदार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और सड़क की मरम्मत तत्काल कराने के निर्देश दिए। यह घटना रविवार की बताई जा रही है, जब गडकरी ने वर्धा जिले के सिंदी शहर में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी थी। यह परियोजना 150.42 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसका निर्माण महाराष्ट्र एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) का संयुक्त उद्यम है।



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गडकरी के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरी तरह विकसित होने के बाद यह पार्क सड़क और रेल के जरिये माल ढुलाई को सुगम बनाएगा। इससे रसद लागत और परिवहन में लगने वाला समय कम होगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही इससे भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम से इतर एक स्थानीय विधायक ने वर्धा की एक सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत केंद्रीय मंत्री गडकरी से की।

नवीन पटनायक के गुमशुदा पोस्टर से ओडिशा में सियासी घमासान

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा की राजनीति में एक नया सियासी घमासान शुरू हुआ है, जब गंजाम जिले के हिंजिली में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक नवीन पटनायक के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे। इस घटना ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी बीजू जनता दल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर छेड़ दिया है। पोस्टर सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं.....आखिर इन पोस्टरों के पीछे कौन है और इसका असली मकसद क्या है? माना जा रहा है कि इन पोस्टरों का संबंध चक्रवात और हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद हिंजिली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सीएम पटनायक की कथित गैरमौजूदगी से है। पटनायक हिंजिली सीट से विधायक हैं, और उस समय में जब गंजाम जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था और राज्य को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था (जिससे 13 लाख लोग प्रभावित हुए थे), उनकी क्षेत्र में अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, पोस्टर लगाने वालों की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है, और न ही किसी व्यक्ति या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिससे इसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य अस्पष्ट बना हुआ है। इस घटना ने भाजपा और बीजेडी के बीच राजनीतिक बयानबाजी को तेज किया है। सत्ताधारी भाजपा पूर्व सीएम पटनायक की हिंजिली में कथित अनुपस्थिति पर लगातार सवाल उठा रही है, जबकि विपक्षी बीजेडी अपने नेता का बचाव कर रही है। बीजेडी का कहना है कि पटनायक ने पार्टी नेताओं और प्रशासन के साथ समन्वय के माध्यम से राहत और सामान्य स्थिति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इन गुमशुदा पोस्टरों के पीछे किसका हाथ है और इसका राजनीतिक या अन्य क्या मकसद है। लेकिन इतना तय है कि हिंजिली में लगे इन पोस्टरों ने ओडिशा की राजनीति में चक्रवात के बाद राहत कार्यों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर एक नई बहस को केंद्र में ला दिया है।

राजधानी दिल्ली में पटाखों की अवैध बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की अवैध बिक्री पर केंद्र सरकार से तत्काल एक्शन लेने को कह दिया है। पटाखों की ब्रिकी पर पाबंदी के बावजूद राजधानी के बाजारों में विभिन्न प्रकार के पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री पर न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अखबार की खबर का संज्ञान लेकर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए।



न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, आज की खबर में एक तस्वीर है, जिसमें दिखाया गया है कि हमारे आदेश के बावजूद दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बाजार में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं, चाहे वे लाइसेंस प्राप्त हों या बिना लाइसेंस वाले, उन पर क्यूआर कोड हो या नहीं। न्यायालय ने इस स्थिति पर तुरंत ध्यान देने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली (7 और 8 नवंबर) पर सुबह छह से सात बजे और रात आठ से 10 बजे तक केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। हालांकि, न्यायालय ने अपने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि पूर्ण प्रतिबंध आदर्श समाधान प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान में उसके पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि यह तय किया जा सके कि प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्ण प्रतिबंध ही सबसे बेहतर विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या पर चिंता जताकर कहा कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष गतिविधि में शामिल होने का अधिकार, भले ही उसका धार्मिक पहलू हो, पूर्ण नहीं है और यह संवैधानिक पाबंदियों से आगे नहीं हो सकता। न्यायालय ने पहले के निर्देशों को लागू करने में अधिकारियों द्वारा बरती गई ढिलाई पर नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने स्पष्ट किया कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित ध्वनि निषेध क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। इन क्षेत्रों को पटाखा-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उनकी विधिवत निशानदेही की जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया के करीब 75 फीसदी लोगों ने माना, 'एक साल में देश और बंटा'

सिडनी , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की खाई बढ़ती जा रही है। एक नए सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। करीब तीन-चौथाई नागरिकों ने माना कि उनका देश पिछले एक साल में पहले के मुकाबले अधिक बंट गया है। इसके साथ ही सरकार, राजनीतिक दलों और नेताओं पर जनता का भरोसा भी कमजोर हुआ है। स्वतंत्र थिंक टैंक मैकिनॉन की ने ये सर्वे कराया। सर्वेक्षण में 41.9 प्रतिशत लोगों ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 12 महीनों में अधिक विभाजित हुआ है, जबकि 32.5 प्रतिशत ने इससे कुछ हद तक सहमति जताई। इस तरह कुल 74.4 प्रतिशत लोगों ने देश में बढ़ते विभाजन को महसूस किया। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर संतुष्ट लोगों की



संख्या भी घटी है। वर्ष 2025 में 28.8 प्रतिशत लोगों ने खुद को बहुत या कुछ हद तक संतुष्ट बताया था, लेकिन 2026 में यह आंकड़ा घटकर 26.1 प्रतिशत रह गया। वहीं, देश की दिशा को लेकर पूरी तरह असंतुष्ट लोगों की संख्या में 7.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, जून और जुलाई में हुए इस सर्वेक्षण में 4,000 से अधिक लोगों से ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था, नेताओं और संस्थानों को लेकर उनकी राय पूछी गई। सर्वेक्षण में संघीय नेताओं और राजनीतिक दलों पर भरोसे में गिरावट भी सामने आई। वर्ष 2025 में 35.9 प्रतिशत लोगों ने संघीय राजनेताओं पर पूरा भरोसा जताया था, जो 2026 में घटकर 30.5 प्रतिशत रह गया। राजनीतिक दलों पर पूरा भरोसा रखने वालों का अनुपात भी 31.2 प्रतिशत से गिरकर 24.4 प्रतिशत पर आ गया। मैकिनॉन के अंतरिम कार्यकारी अध्यक्ष और विक्टोरिया राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री जॉन थ्वेट्स ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा उस राजनीति के मुकाबले कहीं अधिक है, जो इन संस्थाओं के भीतर संचालित होती है। उन्होंने शिक्षा के आधार पर लोकतंत्र के प्रति संतुष्टि में अंतर को भी महत्वपूर्ण बताया। थ्वेट्स के अनुसार, 'विश्वविद्यालय की डिग्री या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों में लोकतंत्र से संतुष्टि का स्तर 59 प्रतिशत है, जबकि हाईस्कूल या उससे कम शिक्षा वाले लोगों में यह केवल 39.7 प्रतिशत है। सर्वेक्षण में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी असंतोष सामने आया। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है।

अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बड़ी दस्तक, 57 चेहरे मंगलवार को आजमाएंगे किस्मत

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में इस बार भारतीय मूल के उम्मीदवारों की उल्लेखनीय मौजूदगी देखने को मिल रही है। ओहायो में गवर्नर पद से लेकर लॉस एंजिलिस के मेयर और मैसाचुसेट्स की सीनेट सीट तक, भारतीय मूल के 57 उम्मीदवार मंगलवार को मतदाताओं के बीच अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह संख्या अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की बढ़ती भागीदारी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करती है। आईएएनएस ने देशभर से जुटाई एक लिस्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इन 57 उम्मीदवारों में एक सीनेट, 11 प्रतिनिधि सभा, तीन राज्यव्यापी पदों, 36 राज्य विधानमंडलों और छह स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सूची में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिनकी भारतीय मूल की पहचान की पुष्टि हो सकी है।

इसके अलावा 15 ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्हें भारतीय मूल का माना जा रहा है, लेकिन पर्याप्त पुष्टि नहीं होने के कारण सूची में जगह नहीं मिली है। इन चुनावों में सबसे अधिक निगाहें ओहायो पर रहेंगी, जहां रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन को चुनौती दे रहे हैं।

रविवार को उपलब्ध फिफ्टीप्लसवन के पोलिंग औसत में एक्टन को करीब तीन अंकों की बढ़त दिखाई गई। रामास्वामी की उम्मीदवारी इसलिए भी अहम है क्योंकि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और उनकी जीत अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की स्थिति को एक



नई ऊंचाई दे सकती है। लॉस एंजिलिस में सिटी काउंसिल सदस्य नित्या रमन मौजूदा मेयर करेन बास को चुनौती दे रही हैं। यूसी बर्कले इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंटल स्टडीज और लॉस एंजिलिस टाइम्स के संयुक्त सर्वेक्षण में दोनों उम्मीदवारों को 40-40 प्रतिशत समर्थन मिला, जबकि 19 प्रतिशत मतदाता अब भी अनिर्णीत थे। यह मुकाबला भी भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बढ़ती राजनीतिक पहुंच का एक अहम उदाहरण है। न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन उम्मीदवार सरिता कोमाटिरेड्डी अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ मैदान में हैं। 28 अक्टूबर को जारी सिएना सर्वेक्षण में जेम्स को 54 प्रतिशत और कोमाटिरेड्डी को 39 प्रतिशत समर्थन मिला था। मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर भी दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वह गवर्नर पद के उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में हैं, जबकि रिपब्लिकन टिकट में डैन कॉक्स शामिल हैं। सीनेट की एकमात्र भारतीय मूल के उम्मीदवार वाली दौड़ मैसाचुसेट्स में है। यहां शिवा अय्यादुरई निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में डेमोक्रेटिक सीनेटर एड मार्की को चुनौती दे रहे हैं।

अरब पार्टियों ने याशार को समर्थन दिया; चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजनकोट के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं। इजराइली मीडिया आई24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने इस गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं, अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम ने आइजनकोट की याशार पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। दरअसल, 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 120 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। नेतन्याहू की पार्टी लिकुड 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मुख्य विपक्षी पार्टी याशार 21 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। लिकुड के गठबंधन की 53 और याशार के गठबंधन की 48 सीटें हैं। अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। अब अगर याशार पार्टी अरब पार्टियों के साथ गठबंधन बनाती है तो उनके पास 67 सीटें हो जाएगी।

नेतन्याहू सभी विकल्पों पर विचार कर रहे : इजराइली मीडिया द्व24 न्यूज के मुताबिक, नेतन्याहू की पार्टी लिकुड के करीबी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वे आइजनकोट के साथ गठबंधन की संभावना को भी खारिज नहीं कर रहे हैं,



जबकि सार्वजनिक रूप से वे साझा सरकार बनाने की योजना से इनकार कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू को चिंता है कि आइजनकोट अरब पार्टियों और कट्टरपंथी यहूदी धार्मिक दलों के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। इससे उन्हें सत्ता से हटना पड़ सकता है।

विपक्षी दलों का समर्थन लेना : नेतन्याहू विपक्षी गठबंधन में शामिल कुछ दलों या सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष के पास कुल 48 सीटें हैं। अगर इनमें से कुछ दल या सांसद नेतन्याहू का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, तो वे बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं।

चुनौती- विपक्षी नेताओं ने चुनाव में नेतन्याहू को सत्ता से हटाने का वादा किया था। ऐसे में उनके लिए अब नेतन्याहू का समर्थन करना आसान नहीं होगा।

राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना : नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बना सकते हैं। इसमें अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। चुनौती- नेतन्याहू के कुछ सहयोगी भी इस विकल्प पर चर्चा कर चुके हैं। इससे नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का मौका मिल सकता है। लेकिन आइजनकोट पहले ही नेतन्याहू के नेतृत्व का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच सहमति बनना मुश्किल हो सकता है।

अल्पमत सरकार बनाना : नेतन्याहू अल्पमत सरकार बनाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसी सरकार के पास अपने गठबंधन में 61 सांसद नहीं होते। इसके बावजूद वह संसद में दूसरे दलों के समर्थन या उनके विरोध न करने के भरोसे चल सकती है।

चुनौती- ऐसी सरकार को बजट पास कराने, विश्वास मत जीतने और दूसरे जरूरी फैसलों के लिए बार-बार दूसरे दलों का समर्थन जुटाना पड़ता है। इसलिए अल्पमत सरकार बनाना ही नहीं, उसे लंबे समय तक चलाना भी मुश्किल होगा। आइजनकोट अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम के समर्थन से सरकार बना सकते हैं। विपक्षी गठबंधन की 48 और अरब पार्टियों की 19 सीटें मिलाकर उनके पास 67 सांसदों का समर्थन है। यह बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से ज्यादा है। आइजनकोट और अरब पार्टियों के बीच कई नैतिक मतभेद हैं। साथ ही नेतन्याहू भी इसे देश के साथ गद्दारी बता चुके हैं।

नेक्सटऐज मीडिया एंड कांलटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, प्रकाशक, संपादक अनीता यादव द्वारा मुद्रक, रजनी कुमारी मेसेर्स साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85 सेक्टर-06 201301 से मुद्रित कराकर 962 सरफाबाद सेक्टर-73, नोएडा-201304 से प्रकाशित किया,
प्रधान संपादक : रिंकू यादव संपादक : अनीता यादव PRGI No. UPHIN/26/A8255 Ph. : 4403949, Email : unplugindia26@gmail.com